RNI No. : TNHIN/2013/52520 ■ वर्ष - 13 ■ अंक - 297 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » मंगलवार » 26-05-2026 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 प्रधानमंत्री का अहंकार तोड़ देगा 'जेन जेड': कांग्रेस

6 देश व समाज हित में है डीजल व पेट्रोल की बचत की मांग!

7 मौनी रॉय ने अपने अंदाज में कान्स को कहा अलविदा

फर्स्ट टेक

पंजाब में पांच किलोग्राम हेरोइन के साथ पंजाबी गायक गिरफ्तार

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब पुलिस ने एक पंजाबी गायक को उसके पास से पांच किलोग्राम हेरोइन और 1.50 लाख रुपये नकद बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, उक्त गायक कथित तौर पर मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले एक नेटवर्क में कूरियर (मादक पदार्थ पहुंचाने वाले) के रूप में काम कर रहा था। बीती सात मार्च के मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले की जांच के बाद हरवीर सिंह सोहल को 5.1 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया और उसकी कार जब्त कर ली गई। सोहल को इससे पहले 2022 में मोहाली पुलिस ने जबरन वसूली के एक रैकेट में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। सोहल अमृतसर के भिंडी सैदां गांव का रहने वाला है और वर्तमान में मोहाली के खरड़ में रह रहा था।

अमिताभ बच्चन ने अस्पताल में भर्ती होने की अफवाहों को खारिज किया

नई दिल्ली/भाषा। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुंबई स्थित अपने घर 'जलसा' के बाहर प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए अपने अस्पताल में भर्ती होने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। दरअसल, पिछले हफ्ते खबरें आई थीं कि अभिनेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उन्होंने बंगले के बाहर अपने प्रशंसकों से मिलकर इन खबरों का खंडन किया है। वे वर्षों से चली आ रही अपनी रविवार की दर्शन की परंपरा को जारी रखे हुए हैं। हर रविवार को हजारों प्रशंसक उनके बंगले के पास इकट्ठा होते हैं। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में अभिनेता सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक प्रशंसकों को हाथ हिला रहे हैं।

आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के घने जंगलों में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश में चलाया जा रहा अभियान लगातार तीसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा और सुरक्षा बलों ने संक्षिप्त गोलीबारी के बाद एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त दल द्वारा शनिवार को 'ऑपरेशन शेरूवाली' शुरू किए जाने के बाद डोरीमल-गंभीर मोगला क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया, ''संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश का अभियान कड़े घेराबंदी के बीच जारी है।

राष्ट्रपति ने 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किये

अभिनेता धर्मेंद्र, वायलिन वादक एन राजम सम्मानित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत और शास्त्रीय संगीतकार एवं वायलिन वादक एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया जिसे उनकी पत्नी और भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने ग्रहण किया। दर्शकों के बीच बैठी उनकी बेटी अहाना देओल इस दौरान भावुक हो गईं।

राजम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अहम योगदान के लिए, खासकर 'गायकी अंग' शैली के माध्यम से वायलिन प्रस्तुति को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया।

मुर्मू ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी; चुनौतियों का सामना कर रहे पारंपरिक भारतीय कला 'अवधान' को पुनर्जीवित करने वाले शतावधानी आर गणेश; कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय सुरेश कुमार कोटक; और उदर रोग विशेषज्ञ कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया।

राष्ट्रपति ने विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे और पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा को भी मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा। पांडे की पत्नी और मल्होत्रा के बेटे ने सम्मान प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। इनमें पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। सोमवार को आयोजित समारोह में उन्होंने दो पद्म विभूषण, छह पद्म भूषण और 58 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। सूत्रों के अनुसार, शेष पद्म पुरस्कार बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।

गुलमर्ग में 'गंडोला' में खराबी

केबल कार में फंसे सभी 300 पर्यटक बचाए गए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में सोमवार को एशिया की सबसे ऊंची केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी आने के बाद घंटों तक आसमान में फंसे रहे 65 केबिन में सवार लगभग 300 पर्यटकों को सात घंटे तक चले कठिन अभियान में बचा लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सात घंटे तक चले एक बड़े बहु-एजेंसी बचाव अभियान के तहत सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रियों को सुरक्षित निकाले जाने को लेकर आपदा राहत बलों के शौर्य एवं कौशल की प्रशंसा की।

अधिकारियों ने बताया कि कुछ केबिन से लोगों को निकालने में अधिक समय लगा, क्योंकि वे जमीन से लगभग 500 फुट की ऊंचाई पर थे। इलाके में भारी बारिश से भी बचाव कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई।

एक अधिकारी ने आज शाम बताया, ''बचाव अभियान समाप्त हो गया है और सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।'' उन्होंने बताया कि प्रणाली में खराबी के कारण गुलमर्ग केबल कार सेवा का संचालन दोनों तरफ से रोक दिया गया था। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस केबल कार सेवार को 'गंडोला' के नाम से जाना जाता है। अधिकारियों के मुताबिक, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के कर्मियों के साथ-साथ पुलिस एवं सेना ने बचाव कार्य में हिस्सा लिया। प्रशिक्षित टीमों ने रस्सियों और सीढ़ियों का उपयोग करके पर्यटकों को सुरक्षित रूप से नीचे उतारा। उन्होंने बताया कि केबल कार प्रणाली को बहाल करने का काम फिलहाल जारी है।

मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय का फैसला

तमिलनाडु में सीमांत किसानों का 50,000 रुपए का फसल ऋण माफ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

आधिकारिक बयान के मुताबिक, एक मई, 2025 से 28 फरवरी, 2026 के बीच सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण इस योजना के तहत माफ किए जाएंगे।

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने सोमवार को राज्य के सीमांत किसानों के लिए सहकारी बैंकों से लिए गए 50,000 रुपए तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की। इसके साथ राज्य के बड़े किसानों के लिए भी 5,000 रुपए तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्य के 14.22 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और सरकार पर 2,044 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। नवगठित राज्य सरकार का यह कदम पिछले महीने विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए चुनावी वादों में शामिल था। आधिकारिक बयान के मुताबिक, एक मई, 2025 से 28 फरवरी, 2026 के बीच सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण इस योजना के तहत माफ किए जाएंगे।

बयान में कहा गया, राज्य सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने फसल ऋण माफ करने का आदेश दिया है।

10 करोड़ रुपए से अधिक के तेंदू पत्ते जलकर खाक

बीजापुर/भाषा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वन विभाग के एक गोदाम में आग लगने से 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के तेंदू पत्ते जलकर राख हो गए। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। बीजापुर के वन मंडल अधिकारी रमेश कुमार जांगड़े ने बताया कि ईटपाल गांव स्थित तेंदू पत्ता भंडारण केंद्र में सोमवार अपराह्न करीब 2:30 बजे आग लग गई। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया।

भारत में अब तक इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया : नड्डा

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में अब तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने भारत में बीमारी के किसी भी प्रसार को रोकने के लिए तैयारियों और निगरानी के उपायों की समीक्षा की। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में नड्डा ने इबोला को लेकर दुनिया भर में चिंता के बीच देश की तैयारी का आकलन किया और निर्देश दिया कि रोकथाम के सभी तरीके पूरी तरह से प्रभावी रहें। बयान में कहा गया है कि मंत्री के निर्देश पर, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तालमेल और तैयारी के उपायों को मजबूत करने के लिए संबंधित विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नड्डा ने अधिकारियों को देश भर में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और भूमि सीमा पार करने सहित देश के सभी प्रवेश बिंदुओं पर इबोला स्क्रीनिंग व्यवस्था को पूरी तरह से सतर्क और मजबूत रखने का निर्देश दिया।

पेट्रोल के दाम 2.61 रुपए, डीजल के दाम 2.71 रुपए बढ़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

संघर्ष के शुरुआती ढाई महीनों में तेल कंपनियों ने लागत बढ़ने के बावजूद खुदरा कीमतों को स्थिर रखा था।

सरकार ने इसे उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने का कदम बताया था, जबकि विपक्षी दलों ने सरकार पर पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी टालने का आरोप लगाया था।

नई दिल्ली/भाषा। देश में सोमवार को पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की गई। यह पिछले दो हफ्तों से भी कम समय में चौथी वृद्धि है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ उसके खुदरा दाम बढ़ा रही हैं। इस ताजा बढ़ोतरी के साथ, 15 मई से लेकर पेट्रोल और डीजल के दामों में कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव और परिवहन लागत बढ़ने की आशंकाएं तेज हो गई हैं।

उद्योग सूत्रों के अनुसार, कीमतों में हुए इस ताजा संशोधन में पेट्रोल 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपए से बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपए से बढ़कर 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गई है।

इस ताजा बढ़ोतरी के बाद मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए और डीजल 97.83 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 113.51 रुपए और 99.82 रुपए प्रति लीटर, जबकि चेन्नई में 107.77 रुपए और 99.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

इससे पहले, 15 मई को पेट्रोल और डीजल में तीन-तीन रुपए प्रति लीटर, 19 मई को 90 पैसे प्रति लीटर तथा 23 मई को पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी।

प्रधानमंत्री के मितव्ययिता के आह्वान का सीतारामन ने किया बचाव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हमें यह समझना चाहिए कि चुनौतियां बाहरी कारकों से अधिक प्रभावित हैं। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति आज भी सकारात्मक और मजबूत बनी हुई है।

मुंबई/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईंधन बचत समेत मितव्ययिता के अन्य उपायों के आह्वान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा... इन तीन मुख्य कारकों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

सीतारमण ने यहां सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) के 37वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री की अपील के बाद नकारात्मक और निराशावादी विमर्श गढ़ने वालों पर भी निशाना साधा और और कहा कि इस समय भारत भय फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। वित्त मंत्री ने कहा कि यह संकट बाहरी घटनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है और घरेलू अर्थव्यवस्था सकारात्मक तथा मजबूत बनी हुई है।

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री की मितव्ययिता की अपील के बाद आदतन आलोचना करने वाले लोगों ने एक नकारात्मक और निराशावादी विमर्श गढ़ा है। ऐसी टिप्पणियां तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। उन्होंने कहा, ''यह (विमर्श) गलत है क्योंकि यह अफवाह के जरिये भय फैला रहा है। भारत भय फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। हमें अपने शब्दों और कार्यों से लोगों को विश्वास दिलाना होगा।''

सीतारमण ने कहा कि ईंधन की कीमतें ऊंची हैं, सोने के दाम भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे बाहरी मोर्चे पर चिंताएं बढ़ गई हैं। उर्वरकों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मितव्ययिता की अपील की है। उन्होंने कहा, ''इसलिए, विदेशी मुद्रा के संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मौजूदा स्थिति में ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा (तीन एफ) पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।''

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की नीति को घरेलू वृद्धि को बनाए रखने के लिए सूझ-बूझ के साथ तैयार किया गया है। डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर एक लाख करोड़ रुपए का असर होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद कुछ आलोचक इस बहस में कूद पड़े हैं। वे दावा कर रहे हैं सब कुछ 'बिखर' रहा है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।

रूबियो ने भारत-विरोधी बयानबाजी के आरोपों को नहीं दी तवज्जो

कहा- 'ट्रंप मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने देश में भारत-विरोधी बयानबाजी की घटनाएं बढ़ने के आरोपों को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं।

यह बयान उस विवाद की पृष्ठभूमि में आया, जो रविवार को एक पत्रकार के सवाल पर रुबियो की प्रतिक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद शुरू हुआ। पत्रकार ने अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ कथित नस्लभेद के मामलों पर सवाल पूछा था।

हालांकि पत्रकार ने साफ नहीं किया, लेकिन कई लोगों ने इसे ट्रंप की उन टिप्पणियों से जोड़कर देखा जिनमें उन्होंने भारत और चीन को ''नरक'' कहा था और वह दोनों देशों के लोगों पर अमेरिका की जन्मजात नागरिकता के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए नजर आए।

अमेरिका के विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर हैं।

26-05-2026 सूर्यास्त 6:30 बजे | 27-05-2026 सूर्योदय 5:41 बजे

BSE	NSE
76,488.96 (+1,073.61)	24,031.70 (+312.40)

सोना	चांदी
16,411 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	281,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

पक्ष-विपक्ष

सत्ता जिसको भी ठीक कहे,
प्रतिपक्ष उसे अनुचित कहता।
सच्चाई पर सहमति के बिन,
भटकाव बना हरदम रहता।
कमजोर तर्क की नींवों पर,
जो महल बना जल्दी ढहता।
उम्मीद लगाए जन मानस,
परिवर्तन धारा में बहता।।

दक्षिण भारत

संत दर्शन एवं निवेदन

जैन विश्व भारती लाडनूं के प्रतिनिधियों ने बेंगलूरु के कनकपुरा स्थित आर्ट ऑफ़ लिविंग परिसर में उसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर से शनिवार को मुलाकात कर उन्हें उनके 70वें जन्मदिवस एवं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर तेरापंथ महासभा के प्रकाश लोढ़ा ने रविशंकरजी को आचार्य महाश्रमणजी के लाडनूं योगक्षेम वर्ष के प्रवास एवं विभिन्न भावी कार्यक्रमों के बारे में बताया और उन्हें आध्यात्मिक मिलन हेतु लाडनूं पधारने का निवेदन किया। इस अवसर पर तुलसी चेतना केंद्र के संगठन मंत्री विक्रम दुगड़, जितेंद्र घोषल, महिला मंडल से ममता घोषल, रंजीता दुगड़ आदि उपस्थित थे।

बैंक कारोबारों की जरूरतों के अनुरूप कर्ज विकल्प विकसित करें : सीतारमण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बैंकों से मानक ऋण उत्पादों से आगे बढ़कर ऐसे कर्ज विकल्प विकसित करने का आग्रह किया जिनकी अदायगी संबंधित कारोबार की जरूरतों एवं आय चक्र के अनुरूप हो।

सीतारमण ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के 37वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि गैर-मानक कारोबार के लिए एक ही तरह के ऋण उत्पाद उपयुक्त नहीं हो सकते हैं और इस दिशा में सिडबी जैसे संस्थान अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, मानक ऋण उत्पाद गैर-मानक कारोबार के लिए काम नहीं कर सकते। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विभिन्न व्यवसायों की आय अलग-अलग समय और तरीके से होती है, जबकि अभी कर्ज की अदायगी आम तौर पर मासिक आधार पर तय होती है।

वित्त मंत्री ने कहा, ''कृषि से जुड़े उद्यमों की आय हर महीने नहीं होती, पर्यटन क्षेत्र में कमाई कुछ महीनों में केंद्रित रहती है, जबकि निर्यातकों को भुगतान में समय लगता है। ऐसे में सभी के लिए एक समान पुनर्भुगतान संरचना रखना उचित नहीं है।'' उन्होंने सुझाव दिया कि नासिक, सतारा और सांगली जैसे क्षेत्रों में स्थित कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कर्ज अदायगी को फसल चक्र से जोड़ा जा सकता है। वहीं, महाबलेश्वर, माथेरान और लोनावला जैसे पर्यटन

स्थलों में ऋण भुगतान को मौसमी आय के अनुरूप तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर कपड़ा और परिधान इकाइयों के लिए निर्यात चक्र को ध्यान में रखते हुए निर्यात-पूर्व एवं निर्यात-पश्चात वित्त के साथ मुद्रा जोखिम से सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। सीतारमण ने कहा, सही उद्यम को सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए सही ऋण उपलब्ध कराना होना चाहिए। उन्होंने सिडबी से केवल ऋणदाता के बजाय छोटे उद्यमों के लिए 'बाजार निर्माता' एवं जोखिम-साझेदार की भूमिका निभाने और स्टार्टअप कंपनियों की ऋण पूंजी जरूरतों को पूरा करने को भी कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में लगभग 32 करोड़ लोग एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत हैं और इस क्षेत्र को सही कर्ज उपलब्ध कराने से व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।

वैश्विक उर्वरक कीमतों में 'अकल्पनीय' उछाल, '3एफ' पर ध्यान देने की जरूरत : सीतारमण

मुंबई/भाषा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बाद वैश्विक उर्वरक कीमतों में अकल्पनीय उछाल आया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मितव्ययिता की अपील का समर्थन करते हुए उन्होंने लोगों से मौजूदा हालात में '3एफ' -- ईंधन (फ्यूल), उर्वरक (फर्टिलाइजर) और विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) -- पर ध्यान देने को कहा। यहां सिडबी के 37वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट केवल एक कूटनीतिक या भू-राजनीतिक मसला नहीं है, बल्कि इसका आम लोगों और छोटे व्यवसायों पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है और यह भारत सहित अन्य देशों के लिए भी एक चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह संकट, जो फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले के साथ शुरू हुआ था, 80-90 दिन से जारी है और इसका असर जिंस कीमतों पर पड़ा है। संघर्ष शुरू होने के बाद से लगभग तीन महीनों तक कच्चे तेल की कीमतें ऊंची और अस्थिर रही हैं, जबकि उर्वरक की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। उर्वरक की कीमतों में 'अकल्पनीय वृद्धि' हुई है। मंत्री ने कहा कि सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि इस कीमती धातु को खरीदने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है।

बीड के प्याज किसान को फसल के लिए मिला सिर्फ 50 पैसे प्रति किलो का दाम

छत्रपति संभाजीनगर/भाषा। महाराष्ट्र के बीड के एक किसान ने सोमवार को दावा किया कि उसे अपनी प्याज की फसल के लिए सिर्फ 50 पैसे प्रति किलोग्राम के दाम मिले हैं। इसके चलते किसानों को बहुत ज्यादा तनाव झेलना पड़ रहा है। बीड के अरणवाड़ी इलाके के भास्कर शिंगारे ने बताया कि वह 22 मई को अपनी 602 किलोग्राम प्याज की खेप सोलापुर की कृषि उपज मंडी समिति में ले गए थे और उन्हें इसके लिए 301 रुपए मिले। उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, ''मजदूरी, परिवहन वगैरह मिलाकर उत्पादन की कुल लागत 1,382 रुपए आई। इसलिए, मुझे अपनी जेब से 1,082 रुपए देने पड़े। मैंने पहले एक छोटा ट्रैक्टर खरीदा था और इस रकम से उसकी मासिक किस्त चुकाने वाला था। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है।'' इतनी कम कीमतों की वजह से किसान इतने बेबस हो गए हैं कि सरकार को जल्द दखल देना चाहिए।

शहरी सहकारी बैंकों में लगातार 10 साल तक ही रह सकेंगे निदेशकः आरबीआई

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के निदेशकों के कार्यकाल से संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति निदेशक मंडल में लगातार 10 साल से अधिक समय तक निदेशक नहीं रह सकता है। केंद्रीय बैंक ने जारी संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा कि 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद किसी निदेशक की दोबारा नियुक्ति तीन साल के अनिवार्य 'कूलिंग-ऑफ' अवधि के बाद ही हो सकेगी। आरबीआई ने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक कानूनी प्रावधानों को दरकिनार कर निदेशक मंडल में बने रहने के लिए बीच में इस्तीफा देकर जल्द ही फिर से निर्वाचित या सह-नामित हो जाते थे। इससे वे निर्धारित अवधि से अधिक समय तक पद पर बने रहते थे। नए नियमों के तहत, अनिवार्य अंतराल (कूलिंग-ऑफ) की अवधि में संबंधित व्यक्ति बैंक से किसी भी रूप में नहीं जुड़ा रहेगा, वह सिर्फ सदस्य या ग्राहक के रूप में जुड़ सकता है। हालांकि, पात्र होने पर वह व्यक्ति कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान किसी अन्य बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक बन सकता है।

जम्मू-कश्मीरः राजौरी में जंगल में आग लगी, विशाल वन क्षेत्र क्षतिग्रस्त

जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा क्षेत्र में सोमवार को जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे जंगल के बड़े हिस्से को व्यापक नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आग रहस्यमय परिस्थितियों में भड़की और शुष्क वनस्पति और मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण तेजी से नौशेरा क्षेत्र के कई इलाकों में फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही, वन विभाग, जम्मू-कश्मीर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमों ने आग पर काबू पाने और उसे आगे फैलने से रोकने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में जंगल का विशाल भूभाग आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पृष्ठभूमि में मोर सहित सैकड़ों पक्षियों की संकटपूर्ण आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस फुटेज ने निवासियों और पर्यावरणविदों के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी है जिन्होंने अधिकारियों से वन्यजीवों को बचाने और आग को जल्द से जल्द बुझाने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने बताया कि दमकल टीमें दुर्गम इलाके में आग पर काबू पाने और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं।

भाजपा ने खरगे के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के उस बयान को लेकर मुख्य विपक्षी दल पर सोमवार को निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कर्नाटक सरकार से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। भाजपा ने कहा कि इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की ''असली ताकत'' किसके पास है।

भाजपा की यह टिप्पणी खरगे के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी आलाकमान से मुलाकात के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री (सिद्दरामय्या) की दिल्ली यात्रा के दौरान गांधी बात करेंगे, न कि वह।

भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि

खरगे ने इस बात को लेकर सभी संदेहों को दूर कर दिया है कि वह केवल एक ''रबर-स्टैंप कांग्रेस अध्यक्ष'' हैं। मालवीय ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि कांग्रेस की कर्नाटक इकाई से जुड़े मुद्दों पर फैसला राहुल गांधी करेंगे। उन्होंने कहा कि खरगे के इस बयान से इस बात को लेकर सभी संदेह दूर हो गये कि वह केवल नाममात्र के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खरगे के बयान से पता चलता है कि कांग्रेस में सत्ता अभी भी गांधी परिवार के पास है।

भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित नेताओं को वास्तविक निर्णय लेने की शक्तियां देने के बजाय उनका ''राजनीतिक फायदे'' के लिए इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा, ''लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का दलितों को वास्तविक शक्ति और स्वायत्तता से वंचित रखते हुए, राजनीतिक सुविधा के अनुसार उनका इस्तेमाल करने का लंबा इतिहास रहा है।''

मालवीय ने अपने आरोप के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार और खरगे का उदाहरण दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में दलित नेताओं को अक्सर प्रतीकात्मक पद दिए जाते हैं जबकि प्रमुख राजनीतिक और संगठनात्मक निर्णय गांधी परिवार के आसपास ही केंद्रित रहते हैं।

राजकोट में बस पलटने से दो महिलाओं की मौत, 20 अन्य घायल

राजकोट/भाषा। गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल कस्बे के पास सोमवार तड़के श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल ले गई एक निजी बस के पलट जाने से एक महिला और उसकी पुत्रवधू की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य लोग घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना गोंडल तालुका के वोराकोटडा गांव के पास सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब बस चालक ने एक संकरी सड़क पर सामने से आ रहे एक ट्रक को रास्ता देने के लिए बस को पीछे किया। पुलिस के अनुसार, करीब 60 श्रद्धालुओं को लेकर बस रविवार सुबह गोंडल से बगदाणा समेत धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए रवाना हुई थी। यह घटना सोमवार को श्रद्धालुओं के लौटते समय घटी। राजकोट ग्रामीण के सहायक पुलिस अधीक्षक प्रखर कुमार ने बताया कि वाहन को पीछे करते समय चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और बस एलिवेटेड रोड के नीचे स्थित एक खेत में पलट गई। उन्होंने कहा, सड़क संकरी है और दो वाहन एकसाथ पार नहीं कर सकते थे। बस चालक ने ट्रक को रास्ता देने के लिए बस को पीछे किया, लेकिन दूरी का गलत अनुमान लगा लिया, जिसके कारण वाहन खेत में पलट गया। कुमार ने बताया कि बस के खेत में पलटने से खिड़की के पास बैठी दो महिलाओं को सिर में गंभीर चोटें आईं।

सीएम ने मेट्रो मंडे से की यात्रा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई 'मेट्रो मंडे' पहल के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों ने सोमवार को मेट्रो और बस से यात्रा की। मुख्यमंत्री राज निवास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से निकटतम मेट्रो स्टेशन पहुंचीं और वहां से मेट्रो से आईटीओ स्टेशन तक गईं। आईटीओ मेट्रो स्टेशन से वह दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस में सवार हुईं और सचिवालय पहुंचीं।

रेखा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, एक बार फिर मैंने सोमवार को दिल्ली सचिवालय जाने के लिए मेट्रो और डीटीसी बस को चुना। इतने सारे दिल्लीवासियों को सार्वजनिक परिवहन को अपनी दैनिक यात्रा का हिस्सा बनाते हुए देखकर मुझे गर्व हो रहा है। उन्होंने कहा, मेट्रो या बस की हर यात्रा और साझा सवारी से यातायात, प्रदूषण और ईंधन की खपत कम करने में मदद मिलती है। एक छोटा कदम, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रभाव। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी तिलक मार्ग स्थित अपने आवास से दिल्ली विधानसभा तक जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया। वहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) की बैठक में शामिल होने के लिए साइकिल से पहुंचे। उच्चतम न्यायालय मेट्रो स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करते हुए, विधानसभा अध्यक्ष ने यात्रियों से बातचीत की और दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। गुप्ता ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईंधन बचत के आह्वान से प्रेरित यह पहल नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने तथा ईंधन बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पहल राष्ट्रीय राजधानी में सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देने, यातायात के बोझ को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के मामले में जनभागीदारी को सशक्त बनाने का भी उद्देश्य रखती है। अपनी यात्रा के दौरान गुप्ता ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो बदली और वहां से विधानसभा मेट्रो स्टेशन तक यात्रा कर दिल्ली विधानसभा पहुंचे।

नीट-यूजी पेपर लीक मामले में नोटिस जारी, उच्चतम न्यायालय ने कहाः एनटीए ने सबक नहीं सीखा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यह दुखद है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने पहले के नीट पेपर लीक से सबक नहीं सीखा है। न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह एक मजबूत और स्वायत्त निकाय स्थापित करने संबंधी याचिकाओं पर केंद्र, एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाओं की प्रति अन्य पक्षों के अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी दी जाए। न्यायालय ने नीट परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एनटीए को 2024 में अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन पर बृहस्पतिवार तक एक हलफनामा दाखिल करने को कहा।

पीठ ने कहा, ''यह दुखद है कि उन्होंने सबक नहीं सीखा है। यह मामला पहले भी इस अदालत में आया था। एक समिति, एक निगरानी समिति गठित की गई थी, जिसने कुछ सिफारिशें की थीं और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। हम चाहते हैं कि एनटीए समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करे।'' शीर्ष अदालत ने फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) द्वारा वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिका

पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस विषय से संबंधित सभी मामलों को एक साथ नत्थी कर रहा है। न्यायालय ने केंद्र द्वारा नियुक्त भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली समिति को एनटीए के कामकाज में सुधार करने और उसके निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को तीन दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की। एफएआईएमए ने बार-बार पेपर लीक होने के कारण 22 लाख से अधिक छात्रों के मौलिक अधिकारों पर ''सीधे सीधे हमला होने'' का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से सीधे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और एनटीए के पुनर्गठन या उसके स्थान पर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के संचालन के लिए एक मजबूत और स्वायत्त प्रणाली की स्थापना की मांग की है। याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि जब तक पुन: परीक्षा की देखरेख के लिए औपचारिक रूप से एक नई समिति का गठन नहीं हो जाता तब तक एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति नियुक्त की जाए।

गडकरी ने राजस्थान, हिमाचल में राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की, मानसून की तैयारियों के निर्देश

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मानसून से पहले प्रभावी जल निकासी प्रबंधन समेत व्यापक तैयारियां पूरी करने के सोमवार को निर्देश दिए। गडकरी ने समीक्षा बैठकों के दौरान राजस्थान में 10,064 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में 1,947 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता तथा रखरखाव की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने टिकाऊ, मजबूत व कुशल राजमार्ग ढांचे के विकास के मकसद से परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा उन्नत तकनीकों और आधुनिक निर्माण तरीकों को अपनाने पर जोर दिया।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संपर्क में सुधार, आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और प्रमुख गलियारों में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत राजमार्ग नेटवर्क महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं को कम करने के मकसद से सड़क सुरक्षा बनाए रखने और परिसंपत्ति की लंबे समय तक मजबूती के लिए प्रभावी जल निकासी प्रबंधन, ढलान संरक्षण कार्यों, सक्रिय निवारक रखरखाव व त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र सहित व्यापक मानसून तैयारी उपायों को अपनाने के निर्देश दिए।

धर्मेंद्र प्रधान 'अक्षम' और 'निकम्मे', प्रधानमंत्री मोदी उन्हें तुरंत बर्खास्त करें : केजरीवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अक्षम और निकम्मा करार देते हुए सोमवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री की वजह से देश भर के लाखों बच्चों को मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। केजरीवाल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मूल्यांकन प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर हिंदी में जारी एक वीडियो संदेश में कहा, सीबीएसई मूल्यांकन में भारी अनियमितताओं ने लाखों बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। इसके

बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, पहले नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) और अब सीबीएसई। प्रधान एक दिन भी शिक्षा मंत्री के पद पर रहने के योग्य नहीं हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कक्षा 10वीं और 12वीं के कई छात्र भारी तनाव में हैं और उनके माता-पिता भी काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा, बच्चों ने पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम किया जाना चाहिए ताकि यह प्रक्रिया हाथ से (मैनुअल) और त्वरित हो सके तथा छात्र समय पर कॉलेज में प्रवेश सुनिश्चित कर सकें। अपने एक मित्र का उदाहरण देते हुए केजरीवाल ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि ऑनलाइन पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है और स्केनिंग फीचर्स पूरी तरह से धुंधले दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, एक अक्षम और निकम्मे शिक्षा मंत्री की वजह से हमारे देश के बच्चों को मानसिक आघात नहीं पहुंचाया जा सकता। मोदी जी कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि शिक्षा मंत्री को तुरंत उनके पद से हटा दें। शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा था कि सीबीएसई अपने परिणाम-पश्चात सेवा पोर्टल में तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास और आईआईटी-कानपुर के विशेषज्ञों की मदद लेगा।

मादक पदार्थ से जुड़े आतंकवाद का खात्मा होने तक हम नहीं रुकेंगेः मनोज सिन्हा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। जम्मू कश्मीर में नार्को-आतंकवाद के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को बांदीपोरा में एक विशाल पदयात्रा का नेतृत्व किया ताकि इसके लिए जनसमर्थन जुटाया जा सके। सिन्हा ने कहा, 45 दिन पहले मैंने यह संकल्प लिया था कि मैं न केवल तस्करों और नार्को-आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करूंगा, बल्कि ऐसा आंदोलन भी शुरू करूंगा जो युवाओं को सशक्त बनाए और नशे से प्रभावित परिवारों की गरिमा बहाल करे।

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर एकजुट है, दृढ़ संकल्पित है और समाज को नशे से पूरी तरह मुक्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक जम्मू कश्मीर की पवित्र धरती से

हर तस्कर खत्म नहीं हो जाता। हमारी एजेंसियों ने उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभूतपूर्व अभियान शुरू किया है। कोई भी मादक पदार्थ तस्कर या समाज को जहर देने वाला अब कानून की पहुंच से बाहर नहीं है। सिन्हा ने कहा कि अब तक छिपे हुए कई मादक पदार्थ नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जम्मू कश्मीर उन लोगों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं होगा जो दूसरों के कष्टों से लाभ कमाते हैं। मैं दृढ़ संकल्पित हूं कि हम इस धरती से हर नार्को-आतंकवादी और मादक पदार्थ तस्कर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार जल्द ही एक व्यापक पुनर्वास नीति लाएगी, जिससे नशे की लत में फंसे युवाओं को मुख्यधारा में लौटने का अवसर मिलेगा। उपराज्यपाल सिन्हा ने 'वकार नॉलेज सेंटर' का उद्घाटन किया, जो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक पुनर्वास पहल है।

हरियाणा में साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

हिसार/भाषा। हिसार पुलिस की साइबर पुलिस स्टेशन टीम ने साइबर धोखाधड़ी में शामिल एक संगठित रैकेट का भंडाफोड़ कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को यहां बताया कि आरोपी लोगों को फोन करते थे और खुद को विभिन्न संस्थानों के अधिकारी बताते थे ताकि उनका विश्वास जीत सकें और फिर धन स्थानांतरित करने और प्रोसेसिंग फीस के बहाने उन्हें विभिन्न बैंक खातों में पैसे जमा करने के लिए प्रेरित करके उनसे धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने यहां बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और साइबर धोखाधड़ी के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और उनसे संबंधित बैंक खातों की जांच जारी है।

विजय ने कर्नाटक से जुड़े मेकेदातु बांध विवाद पर कानूनी कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मेकेदातु में कावेरी नदी पर बांध निर्माण के कर्नाटक के प्रस्ताव पर एक समीक्षा बैठक की। इस परियोजना का तमिलनाडु विरोध कर रहा है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि यह बैठक परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि पूजन की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई।

इसमें कहा गया है, तमिलनाडु के अधिकारों को स्थापित करने और किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया कि बैठक में संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। उच्चतम न्यायालय ने पहले के उस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय के कानूनी दायरे पर केवल केंद्रीय विशेषज्ञ ही निर्णय ले सकते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, मुख्यमंत्री ने उपरोक्त अदालती फैसले को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परामर्श के बाद कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर मेकेदातु में एक संतुलन जलाशय बनाने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य पेयजल और बिजली उत्पादन दोनों उद्देश्यों को पूरा करना है।

तमिलनाडु नदी के निचले हिस्से में स्थित एक राज्य है और उसका कहना है कि यदि यह परियोजना साकार होती है तो वह प्रभावित होगा। मंत्री एन आनंद, आधव अर्जुन और आर निर्मलकुमार के अलावा महाधिवक्ता विजय नारायण भी बैठक में उपस्थित थे।

यौन अपराधों में तुरंत मामले दर्ज करें और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएं : विजय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने सोमवार को पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि यौन अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत मामले दर्ज किए जायें, उनकी तेजी से जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए।

कोयंबटूर में 10 वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न एवं उसकी निर्मम हत्या की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आरोपियों को कठोर दंड दिलाया जाए। यह बैठक टीवीके सरकार के तहत कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष की आलोचना के बीच हुई है। मुख्य विपक्षी दल द्रमुक सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने हाल के समय में हुई हत्याओं और यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं को लेकर टीवीके सरकार पर तीखा हमला किया है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में मुकदमों की सुनवाई तेज की जाए। साथ ही एहतियाती उपाय और जन-जागरूकता भी की जाए।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों से कहा, यौन उत्पीड़न के मामलों की त्वरित सुनवाई होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए, ताकि यह दूसरों के लिए भी निवारक साबित हो। रविवार को मुख्यमंत्री ने फोन पर उस बच्ची के परिवार से बात की जिसकी कोयंबटूर में यौन उत्पीड़न के बाद हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। कोयंबटूर के सुलूर में बच्ची के यौन उत्पीड़न और उसकी निर्मम हत्या की इस घटना ने पूरे तमिलनाडु में आक्रोश पैदा कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री विजय ने शनिवार को सख्त कार्रवाई का वादा किया था। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बच्ची का एक परिचित भी शामिल है। बैठक में मुख्य सचिव एम. साईकुमार, गृह सचिव के. मणिवासन, महाधिवक्ता विजय नारायण, सामाजिक कल्याण एवं महिला अधिकार विभाग की सचिव मरियम पल्लवी बलदेव और पुलिस महानिदेशक संदीप रॉय राठौड़ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

तमिलनाडु : इरोड जिले में बिजली गिरने से एक दंपति बाल-बाल बचे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इरोड/भाषा। तमिलनाडु के इरोड जिले के एक गांव में बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक दंपति की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, गोबिचेट्टीपलयम के पास कोलाप्पलूर गांव के सुरेश (42) और उनकी पत्नी मंजुला (38) एक दूकान चला रहे थे। उन्होंने बताया कि रविवार शाम को भारी बारिश के कारण दंपति ने अपनी दुकान बंद कर दी। जब वह निकलने ही वाले थे कि बिजली उन पर गिरी और दोनों बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत स्थानीय सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

गोबिचेट्टीपलयम पुलिस ने बिजली गिरने से हुई मौत का मामला दर्ज किया है।

अन्नाद्रमुक के तीन बागी विधायकों ने इस्तीफा सौंपा, टीवीके में शामिल होने की संभावना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अन्नाद्रमुक के तीन बागी विधायकों ने इस्तीफा सौंपा, टीवीके में शामिल होने की संभावना

चेन्नई/भाषा। वरिष्ठ नेता सी.वी. षणमुगम और एस.पी. वेलुमणि के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक के बागी गुट से जुड़े तीन विधायकों ने सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष जे.सी.डी प्रभाकर से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इन विधायकों के सत्तारूढ़ टीवीके में शामिल होने की अटकलें हैं।

विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के तुरंत बाद तीनों विधायकों (मदुरंथकम से निर्वाचित एम. कुमारवेल, धारापुरम से निर्वाचित सत्यभामा और पेरुंदुरई से चुने गए जयकुमार) ने टीवीके सरकार में मंत्री आधव अर्जुन से उनके कक्ष में मुलाकात की। माना जा रहा है कि कुमारवेल, सत्यभामा और जयकुमार तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अन्नाद्रमुक के टिकट पर चुनाव जीतने वाले तीनों विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए।

इस बीच, पांच अन्य विधायक षणमुगम-वेलुमणि गुट छोड़कर पार्टी प्रमुख ई.के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले खेमे में वापस चले गए।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर षणमुगम ने संवाददाताओं से कहा, बाद में बात करेंगे।

तीनों विधायकों ने यहां सचिवालय में प्रभाकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। धारापुरम (तिरुप्पुर) और पेरुंदुरई (इरोड) पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगु क्षेत्र में आते हैं और अन्नाद्रमुक के पारंपरिक गढ़ रहे हैं। मदुरंथकम चेन्नई के पास स्थित है।

कुमारवेल, सत्यभामा और जयकुमार उन 25 विधायकों में शामिल थे, जिन्होंने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए मुख्यमंत्री विजय के विश्वास मत हासिल करने के दौरान टीवीके सरकार के समर्थन में मतदान किया था।

इस बीच, षणमुगम-वेलुमणि गुट में शामिल अन्नाद्रमुक के पांच विधायक फिर से पलानीस्वामी के खेमे में चले गए। इसके साथ ही विधानसभा में पलानीस्वामी समर्थक विधायकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई।

वेलुमणि गुट छोड़ने वाले विधायकों में एस.एम. सुकुमार (आर्कोट) भी शामिल हैं।

तीन विधायकों के इस्तीफे और पांच विधायकों के पलानीस्वामी खेमे में लौटने के बाद, बागी गुट में शामिल विधानसभा सदस्यों की संख्या अब 25 से घटकर 17 रह गई है।

विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं, जिसके बाद तमिलनाडु में चार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की संभावना बन गई है। इन सीट में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ओर से खाली की गई तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट भी शामिल है।

विधानसभा अध्यक्ष प्रभाकर ने संवाददाताओं को बताया कि अन्नाद्रमुक के तीनों विधायकों के इस्तीफे तय प्रक्रिया के अनुसार सही प्रारूप में मिले, इसलिए उन्हें स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा, इस्तीफा देने के लिए कारण बताना जरूरी नहीं है।

विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 21 दिन के अंदर अन्नाद्रमुक में इस टूट को पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं, द्रमुक को भी झटका लगा है, क्योंकि उसके सहयोगी दल कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल टीवीके सरकार में शामिल हो गए हैं, जबकि वाम दलों ने विजय के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया है।

इस बीच, अन्नाद्रमुक के षणमुगम गुट का समर्थन करने वाले पांच विधायकों ने पलानीस्वामी के ग्रीनवेज रोड स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की और उनके खेमे में लौट गए। बाद में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर कहा कि वे अब पलानीस्वामी के नेतृत्व में काम करेंगे।

पलानीस्वामी गुट में लौटे विधायकों में एस.एम. सुकुमार (आर्कोट), पी. हरिबास्कर (अंथियूर), दिलीपन जयशंकर (शंकरकोइल), एन.एस.एन. नटराजन (कांगयम) और के. मोहन (पणरुति) शामिल हैं।

सुकुमार ने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा है, जिसमें बहुमत परीक्षण के दौरान हुई कुछ गलतियों पर खेद जताया गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी पांच विधायकों ने पलानीस्वामी के नेतृत्व में काम करने का फैसला किया है।

इस बीच, अन्नाद्रमुक के सांसद और पार्टी के अधिवक्ता विंग के सचिव आई.एस. इन्बादुरई ने तीन विधायकों के इस्तीफे के कदम को विधायकों की खरीद-फरोख्त बताया।

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता पी. विल्सन ने भी टीवीके पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्वाचित विधायकों का 21 दिन में इस्तीफा देकर तुरंत टीवीके में शामिल होने की तैयारी करना दल-बदल कानून से बचने की कोशिश है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकारी सचिवालय परिसर और कार्यालयों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों में शामिल होने के लिए किया जाना अनुचित है।

नेमम में हार के लिए भाजपा से नकदी लेने के आरोप झूठेः शिवनकुट्टी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता एवं केरल के पूर्व मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने सोमवार को खबरों को ''झूठा और बेबुनियाद'' बताकर खारिज कर दिया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि पार्टी के कुछ नेताओं ने नौ अप्रैल के विधानसभा चुनाव में नेमम सीट पर उन्हें हराने के लिए भाजपा से रुपए लिए थे।

एक बयान में माकपा राज्य समिति के सदस्य ने कहा कि ये खबरें पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की छवि खराब करने के इरादे से फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, ''मीडिया के एक वर्ग

में यह खबरें चलाई जा रही हैं कि नेमम में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के उम्मीदवार को हराने के लिए माकपा के कुछ नेताओं ने भाजपा से रुपए लिए जो पूरी तरह झूठ है और तथ्यों से परे है।'' उन्होंने कहा कि ऐसा प्रचार सिर्फ पार्टी और लाखों ईमानदार कार्यकर्ताओं को समाज में बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया संगठन जानबूझकर पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चर्चाओं को तोड़-मरोड़कर ''मनगढ़ंत कहानियां'' फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, ''नेमम और तिरुवनंतपुरम के पार्टी कार्यकर्ता और जनता फासीवादी ताकतों और दक्षिणपंथी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट हैं। दक्षिणपंथी मीडिया लगातार इस राजनीतिक जागरुकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।'' उनका यह बयान उस खबर के एक दिन बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि माकपा के कुछ नेताओं ने नेमम में वाम मोर्चे के उम्मीदवार की हार सुनिश्चित करने के लिए भाजपा से रुपए लिए। नेमम उन तीन विधानसभा सीट में से एक है, जो भाजपा ने नौ अप्रैल के केरल विधानसभा चुनाव में जीतीं।

'ईंधन उपकर पर विचार किया जा रहा है, फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया'

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर को वापस लेने के बारे में सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि ईंधन की कीमतें अब भी काफी अधिक हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मुद्दे की अभी विस्तृत समीक्षा की जा रही है।

सतीशन ने कहा, फिलहाल हम इस मामले पर गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम किसी अंतिम निर्णय की स्थिति में नहीं हैं। स्थिति हर दिन बदल रही है। केरल में वाम दलों की सरकार के दौरान बढ़ती वित्तीय जरूरतों के बीच अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रयास के तहत पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाया गया था।

केरल के मुख्यमंत्री सतीशन का गुरुवायूर मंदिर जाना उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

त्रिशूर/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन के प्रसिद्ध गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर की यात्रा करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि रविवार को मंदिर में 'वीआईपी दर्शन' को लेकर केरल उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया और आम श्रद्धालुओं को असुविधा हुई।

सतीशन ने रविवार को गुरुवायूर मंदिर में पूजा-अर्चना की और पारंपरिक 'तुलाभारम' अनुष्ठान भी किया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता बी गोपालकृष्णन ने गुरुवायूर देवस्वोम प्रशासन को शिकायत देकर आरोप लगाया कि रविवार सुबह प्रतिबंधित समय के दौरान मुख्यमंत्री और उनके साथ आए नेताओं को विशेष वीआईपी दर्शन की सुविधा दी गई। उन्होंने 24 मई को फेसबुक पर एक पोस्ट में दावा किया कि उच्च न्यायालय ने रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है। साथ ही, मंदिर परिसर और मेलपथुर सभागार के आसपास वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर भी प्रतिबंध है।

गोपालकृष्णन ने आरोप लगाया कि सतीशन और उनके सहयोगियों को सुबह करीब साढ़े सात बजे से साढ़े नौ बजे के बीच 4,500 रुपए की अनिवार्य 'श्रीकोविल नेयविलक्कु' रसीद के बिना वीआईपी दर्शन कराया गया। नियमों के अनुसार अवकाश के दिनों में विशेष दर्शन के लिए यह रसीद लेना आवश्यक है।

मंदिर के नियमों के मुताबिक 'नेयविलक्कु' रसीद लेने वाले श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन की अनुमति मिलती है।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद हिबी ईडन सहित कई वीआईपी लोगों ने मना करने के बावजूद मंदिर परिसर के आसपास वीडियो बनाये। उन्होंने शिकायत में कहा, जो लोग कानून की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही उसका उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि देवस्वोम प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

हालांकि, मंदिर का प्रबंधन करने वाले गुरुवायूर देवस्वोम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का दर्शन नियमों के अनुसार कराया गया था।

देवस्वोम ने सोमवार को फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट किया कि रविवार अवकाश का दिन होने के कारण सतीशन ने 4,500 रुपए की 'श्रीकोविल नेयविलक्कु' रसीद लेकर दर्शन किया था।

हालांकि, देवस्वोम की फेसबुक पोस्ट में विवाद का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवायूर देवस्वोम के अध्यक्ष ए वी गोपीनाथ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में अवकाश के दिनों में वीआईपी दर्शन पर रोक है, लेकिन प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री और उनके दल द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किये जाने का मामला नजर नहीं आता।

गोपीनाथ ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ श्रद्धालुओं की ओर से शिकायत मिली है कि मुख्यमंत्री के दौरे के कारण वे पूजा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री रविवार सुबह करीब सात बजे मंदिर पहुंचे थे। पूजा-अर्चना के बाद वह मंदिर परिसर में आयोजित राजस्व मंत्री ए पी अनिल कुमार के पुत्र के विवाह समारोह में भी शामिल हुए।

कोयंबटूर में बच्ची के दुष्कर्म-हत्या का मामला : शव परिवार को सौंपा गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयंबटूर/भाषा। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में 10 साल की उस बच्ची का शव उसके पिता को सौंप दिया गया है, जिसकी हाल में सुलूर के पास कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद हत्या कर दी गई थी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी का अंतिम संस्कार उसकी सहमति के बिना किया गया।

पुलिस महानिरीक्षक (पश्चिम क्षेत्र) राम्या भारती ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता संभवत: एक ही जगह पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा, ''यह स्पष्ट है कि घटना की वजह से उनके बीच कोई घरेलू विवाद हुआ होगा।''

बच्ची की मां ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि पहले उसने न्याय सुनिश्चित होने तक अस्पताल से शव सौंपे जाने से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, उसने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद उसके पति के हस्ताक्षर लेने के बाद बच्ची का शव परिवार को सौंप दिया गया।

बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि परिवार ने उसे अपनी बेटी को आखिरी बार देखने का मौका नहीं दिया और ईएसआई अस्पताल के पिछले दरवाजे से एम्बुलेंस से बच्ची का शव ले जाकर सेलम में उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

यह मामला 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, कथित यौन उत्पीड़न और हत्या से संबंधित है। बच्ची का शव 22 मई को सुलूर के कन्नामपलयम झील के किनारे मिला था, जिस पर चोटों के स्पष्ट निशान थे। 23 मई को जिला पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य संदिग्धों में से एक की पहचान 33 वर्षीय के कार्थी के रूप में हुई, जो परिवार का पड़ोसी था। दूसरे संदिग्ध की पहचान आर मोहन के रूप में हुई।

इस बीच, मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव, गृह सचिव और महाधिवक्ता के साथ इस मामले से संबंधित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, विजय ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों को यौन अपराधों से जुड़े सभी मामलों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए और राज्य अभियोजकों को त्वरित सुनवाई के जरिये शीघ्र एवं कठोर सजा सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

परियाथुकावु बेदखली विवादः केरल सरकार का आश्वासन, कोई भी दलित परिवार बेघर नहीं होगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने सोमवार को कहा कि एर्नाकुलम जिले के परियाथुकावु के निवासियों से जुड़े काफी समय से लंबित विवाद के समाधान के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी दलित परिवार बेघर नहीं होगा। इस मुद्दे से निपटने के तरीके को लेकर वामपंथी दलों की आलोचना के बीच, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सतीशन ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित है कि यदि बेदखली की जाती है तो पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमारा रुख स्पष्ट है। यदि अदालत का आदेश लागू होता है, तो हम वैकल्पिक भूमि और आवास सुनिश्चित करेंगे, ताकि इन परिवारों का पुनर्वास हो सके। हम उन्हें बेघर नहीं होने देंगे।'' सतीशन ने केरल उच्च न्यायालय के एक हालिया निर्देश के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही। उच्च न्यायालय ने पूर्व में एक निजी पक्ष द्वारा हासिल उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक भूमि से बेदखली का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने समझौता विकल्पों और मानवीय राहत उपायों पर विचार करने के लिए महाधिवक्ता सहित वरिष्ठ अधिकारियों और कानूनी प्राधिकारियों के साथ पहले ही चर्चा की है।

सतीशन ने इस मामले में बेदखली आदेशों को लागू करने के पूर्व के प्रयासों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती वामपंथी सरकार लंबे समय से चले आ रहे विवाद को प्रभावी ढंग से हल करने में विफल रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने महाधिवक्ता को प्रभावित परिवारों की

स्थिति पर विचार करने के बाद अदालत से और समय मांगने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए कानूनी निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परियाथुकावु बेदखली मामला एर्नाकुलम के किझाक्कंबलम के पास लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद से संबंधित है, जहां दलित परिवार दशकों से निजी पक्षों द्वारा दावा की गई भूमि पर रह रहे हैं।

एक अदालत ने स्वामित्व विवाद के आधार पर बेदखली का आदेश दिया है, लेकिन बेदखली के बार-बार के असफल प्रयासों और परिवारों के पुनर्वास की मांगों के कारण यह मामला विवादों में घिर गया है। इस मुद्दे ने राज्य में राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी, दोनों पक्ष लंबे समय से चले आ रहे विवाद के लिए एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। माकपा-नीत पूर्ववर्ती वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार पर हमला करते हुए सतीशन ने कहा, ''यह देखकर मैं स्तब्ध रह गया - पिछली कैबिनेट के दो पूर्व मंत्री वहां विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सब हमारी सरकार के शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन बाद हुआ।'' उन्होंने कहा कि निवासियों को बेदखल करने का 15वीं बार प्रयास किया गया था।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ''पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान, बेदखली के लिए अदालत के निर्देश पर 14 बार प्रयास किए गए, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पूर्ववर्ती सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक छोटा सा कदम भी नहीं उठाया।'' उन्होंने कहा, ''यह जमीन से संबंधित एक निजी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया निजी मामला है। अदालत के आदेश को लागू कराने के लिए 14 बार अपील की गई, लेकिन (पूर्ववर्ती एलडीएफ सरकार द्वारा) कुछ नहीं किया गया। हमने सत्ता में आने के ठीक अगले दिन इस पर कार्रवाई की।'' उन्होंने कहा कि सरकार ने तुरंत एर्नाकुलम से उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन को विरोध कर रहे परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के लिए भेजा।

सतीशन ने कहा, ''हमने इस बात का आकलन किया कि क्या किया जा सकता है। हमारा निर्णय यह है कि यदि अदालत का आदेश लागू होता है, तो आठ परिवार बेघर नहीं होने चाहिए।''

संक्षिप्त खबरें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अमेरिका के विदेश मंत्री जयपुर पहुंचे, पत्नी संग देखा आमेर किला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को अपनी पत्नी जेनेट रूबियो के साथ जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किला पहुंचे। सुरक्षाकर्मियों से घिरे रूबियो दंपति का किले में पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। उन्होंने कच्ची घोड़ी और घूमर सहित लोक नृत्यों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखीं। पर्यटक गाइड महेश कुमार शर्मा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि रूबियो का दौरा लगभग आधे घंटे तक चला, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने किले के कई प्रमुख हिस्सों का भ्रमण किया।

उन्होंने कहा, रूबियो को आमेर किले के इतिहास और स्थापत्य महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद वह दीवान-ए-आम पहुंचे, जहां से उन्होंने विशाल किला परिसर और आस-पास का दृश्य देखा। शर्मा ने बताया कि रूबियो ने विशेष रूप से किले की जल प्रबंधन प्रणाली में रुचि दिखाई और पहाड़ी पर स्थित किले में जल आपूर्ति के स्रोत के बारे में पूछा।

अमेरिकी विदेश मंत्री को पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली के बारे में बताया गया, जिसे सुनकर वह सदियों पुरानी इंजीनियरिंग तकनीकों से प्रभावित दिखे। विदेश मंत्री ने गणेश पोल और प्रसिद्ध शीश महल का भी दौरा किया। जयपुर की भीषण गर्मी के बावजूद, रूबियो इस यात्रा का आनंद लेते हुए दिखाई दिए।

पीले और गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित यह किला मुख्य शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। रूबियो की यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वह शनिवार को चार दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे थे। इससे पहले सोमवार को रूबियो ने अपनी पत्नी के साथ आगरा में ताज महल का दौरा किया था। रूबियो मंगलवार सुबह दिल्ली लौटेंगे, जहां वह क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे।

राजस्थान केंद्रीय विवि ने पीएच.डी. शोधार्थियों के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन योजना शुरू की

जयपुर। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शोधार्थियों के हित में पहल करते हुए पीएचडी शोधार्थियों के लिए कुलपति सीयूराज अनुसंधान प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ये यह जानकारी दी। यह योजना न केवल शोधार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें बिना किसी वित्तीय चिंता के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने के लिए प्रेरित भी करेगी। प्रशासन के अनुसार, यह योजना विशेष रूप से नॉन-नेट फेलोशिप प्राप्त शोधार्थियों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र शोधार्थियों को वर्तमान नॉन-नेट फेलोशिप के अतिरिक्त प्रति माह पांच हजार रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शोध संबंधी व्ययों के लिये दस हजार रुपए की अतिरिक्त आकस्मिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' की शुरुआत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को गंगा दशमी के अवसर पर टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध से 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' की शुरुआत की। उन्होंने जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों की जानकारी ली और आमजन से अभियान में सहभागिता निभाते हुए जल संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। उल्लेखनीय है कि 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' के तहत 25 मई से पांच जून तक राज्यभर में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बीसलपुर बांध पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत जल पूजन किया और अच्छी बारिश की कामना की। इसके बाद उन्होंने बीसलदेव महादेव मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की।

इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भी 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान' चलाकर बांधों, तालाबों, सरोवरों और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं सफाई का कार्य कराया था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी आज से अभियान की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, जल ही जीवन है और आमजन की सक्रिय भागीदारी से ही जल संरक्षण अभियान सफल हो सकता है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बीसलपुर बांध की 'स्काडा' प्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि बीसलपुर बांध पूर्वी राजस्थान के जिलों में निर्बाध जलापूर्ति का प्रमुख माध्यम है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बांध क्षेत्र में नई संरचनाओं का निर्माण किया जाए और बनास नदी के पुनर्भरण की दिशा में प्रभावी कार्य किए जाएं, ताकि वर्षाजल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण को मजबूती मिल सके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ईसरदा बांध का हवाई सर्वेक्षण कर जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

गौरतलब है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल ईसरदा, गलवा और बंध बरेठा जैसे तीन प्रमुख बांधों से होकर गुजरता है।

अधिकारियों के अनुसार, अभियान के तहत गांव-गांव में कुओं, बावड़ियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की सफाई, श्रमदान, जल चौपाल, प्रभात फेरी, पौधारोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा नए जल संरक्षण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री की सोच से भिक्षावृत्ति और अवांछित गतिविधियों से जुड़े परिवारों के बच्चों को मिल रही नई पहचान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील और समावेशी सोच को धरातल पर साकार करता कोटा जिले के मंडाना कस्बे में संचालित प्रदेश का एकमात्र भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु राजकीय आवासीय विद्यालय आज सामाजिक परिवर्तन और पुनर्वास की प्रेरणादायक मिसाल बन चुका है। यहां भिक्षावृत्ति और अवांछित गतिविधियों से जुड़े परिवारों के बच्चों ने आम बच्चों की तरह 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा अंक हासिल कर अनूठी मिसाल कायम की है।

राजस्थान का कोटा शहर जहां शिक्षा नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है, वहीं कोटा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित मंडाना कस्बा अब उन बच्चों की सफलता की वजह से चर्चा में है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर हर बच्चा सफलता हासिल कर सकता है।

साधारण परिस्थितियों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 10वीं और 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन मंडाना आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की सफलता इसलिए विशेष है क्योंकि उन्होंने बेहद कठिन हालातों से निकलकर यह मुकाम हासिल किया है। इन बच्चों ने बचपन में सामाजिक तिरस्कार, आर्थिक तंगी और असुरक्षित माहौल देखा है। कई बच्चों के लिए शिक्षा केवल एक सपना थी, लेकिन आज वही बच्चे पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं।

राज्य सरकार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं के सभी 51 विद्यार्थियों ने परीक्षा में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त कर एक प्रेरणादायक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस आवासीय विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सुरक्षित आवास, भोजन, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, खेलकूद और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

इस आवासीय विद्यालय में कुल 238 छात्र अध्ययनरत हैं।इसआवासीय विद्यालय में ऐसा सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण तैयार किया गया है, जहां बच्चे बिना किसी भय या भेदभाव के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा बच्चों को परिवार जैसा स्नेह और मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे उनके व्यवहार, सोच और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। अब ये बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रुचि ले रहे हैं। इस वर्ष विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 10वीं और 12वीं के सभी 51 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर शत-प्रतिशत परिणाम दर्ज किया। 12वीं कक्षा में कुल 20 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 17 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी, 2 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी तथा 1 विद्यार्थी ने तृतीय श्रेणी प्राप्त की। छात्र रमेशचंद ने 87.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया, जबकि जगदीश ने 83 प्रतिशत अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं 10वीं कक्षा में परीक्षा देने वाले सभी 31 विद्यार्थी सफल रहे। इनमें 13 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी तथा 18 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की। नितेश कुमार ने 88.67 प्रतिशत तथा रामलखन ने 86 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की।

बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते उपनिरीक्षक गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी घड़साना थाने में तैनात एक पुलिस उपनिरीक्षक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को बीस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि आरोपी रामेश्वरलाल को ब्यूरो की बीकानेर इकाई ने ट्रैप कार्रवाई के दौरान रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उपनिरीक्षक ने एक मामले में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) दर्ज करने के बदले शिकायतकर्ता से पचास हजार रुपये की मांग की थी। बातचीत के बाद आरोपी ने कथित तौर पर बीस हजार रुपये लेने पर सहमति जताई।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते समय गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि रिश्वत की राशि आरोपी के कब्जे से बरामद कर ली गई है।

इस सप्ताह भीषण गर्मी की चेतावनी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में तेज गर्मी का दौर जारी है और मौसम विभाग ने इस सप्ताह भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के पश्चिमी भागों में वर्तमान में अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 46.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में गर्म रात्रि और धूल भरी हवाएं दर्ज की गईं। इसके अनुसार, इस सप्ताह आगामी 2-3 दिन राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। तेज धूलभरी हवाएं चलेंगी तथा तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की और बढोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 26-27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री दर्ज होने व कहीं-कहीं तीव्र 'ऊष्ण दिन एवं रात्रि' दर्ज होने की पूरी संभावना है।

एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28-29 मई से राज्य के कुछ भागों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आएगी व कहीं-कहीं बारिश का दौर शुरू हो सकताा है। इसके असर से अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार आंधी बारिश की गतिविधियां जून के पहले सप्ताह में भी जारी रहेंगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल्स से सशक्त होंगे प्रदेश के किसान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर । राजस्थान के कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने और पूरी कृषि वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। पंत कृषि भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार तथा देश के प्रतिष्ठित नॉट-फॉर-प्रोफिट संस्थान 'लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी' के मध्य एक महत्वपूर्ण गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस अवसर पर कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में कई बड़े नवाचार कर रही है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 'एग्री-स्टैक' के तहत राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जहाँ निर्धारित लक्ष्य का 95 प्रतिशत पूरा करते हुए प्रदेश के लगभग 95 लाख किसानों की डिजिटल 'फार्मर आईडी' बनाई जा चुकी है। यह फार्मर आईडी केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इसमें किसान के खसरा नंबर, भूमि विवरण और आधार नंबर सहित पूरी क्रेडेंशियल्स दर्ज हैं। इसके माध्यम से आगामी फसल बीमा और एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के तहत यूरिया वितरण जैसी व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाकर इसके दुरुपयोग को पूरी तरह रोका जा सकेगा। आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य में एआई-बेस्ड मॉडल्स और 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना की दिशा में यह एमओयू एक मील का पत्थर साबित होगा। इस साझेदारी के तहत 'वाधवानी एआई' आगामी 3 वर्षों के लिए राज्य सरकार का निःशुल्क तकनीकी भागीदार बनकर कार्य करेगा, जिससे राजकोष पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। इस तकनीक से फील्ड स्तर पर सूचना तंत्र सुदृढ़ होगा और अंतिम छोर पर बैठे

एग्रीवाणी- यह एक बहुभाषी चैटबॉट मॉडल है, जिसमें किसान अपनी ही भाषा में वॉइस या टेक्स्ट के माध्यम से संवाद कर सकेंगे। यह एआई टूल किसानों की समस्याओं को सुनकर तत्काल तकनीकी समाधान प्रदान करेगा।

सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर - स्मार्टफोन आधारित इस ऐप से किसान मंडी जाने से पहले ही अपनी सोयाबीन की फसल की गुणवत्ता, ग्रेडिंग और प्रोटीन आदि का रियल-टाइम आकलन खुद कर सकेंगे, जिससे उन्हें उपज का सही मूल्य मिल सकेगा।

एग्री एआई कलेक्ट व न्यूज मॉनिटरिंग- यह टूल किसानों की फील्ड गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने तथा प्रशासनिक स्तर पर त्वरित निर्णय लेने के लिए कृषि से जुड़ी खबरों की निरंतर मॉनिटरिंग में सहयोग करेगा।इस अवसर पर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जल पूजन, पीपल पूजन व दीपदान के साथ जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान

जयपुर/दक्षिण भारत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में जल संस्कृति सजीव हो रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी 'वंदे गंगा: जल संरक्षण जन अभियान' का सोमवार को चूरू जिले में सेठाणी का जोहड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जल संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल का विशेष महत्व रहा है और गंगा दशमी का यह दिन भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मान्यता अनुसार आज ही के दिन मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में पानी केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और संस्कृति का आधार है।

उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और बिगड़ते पर्यावरणीय हालात के बीच जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना जरूरी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश सरकार हमारी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

ग्रामीण विकास शासन सचिव व चूरू जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि चूरू जिले के परिप्रेक्ष्य में जल संरक्षण और भी अधिक महत्वपूर्ण है। चूरू मरुस्थलीय जिला होने के कारण यहां जल स्रोतों को संरक्षण अधिक आवश्यक हो जाता है।

देवनानी ने गंगा दशहरा पर विधान सभा उद्यान में लगाया कल्पवृक्ष

जयपुर। राजस्थान विधान सभा उद्यान में गंगा दशमी 25 मई,सोमवार से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, शुक्रवार तक प्रतिदिन दो पौधे लगाये जायेंगे। इसके तहत विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधान सभा उद्यान में सोमवार को कल्प वृक्ष का पौधा लगाकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारम्भ किया। विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने भी उद्यान में कल्प वृक्ष का पौधा लगाया। स्पीकर देवनानी ने गंगा दशहरा की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक रहना होगा। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। समाज में सकारात्मक ऊर्जा, भाईचारे और लोक कल्याण की भावना को सुदृढ करता है। देवनानी ने लोगों का आह्वान किया है कि सभी लोग पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभायें।

देवनानी ने कहा कि भारतीय संस्कृति, आस्था और जीवनदायिनी प्रकृति का प्रतीक हैं। गंगा दशमी आध्यात्मिक आस्था के पर्व के साथ जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जनजागरण का भी संदेश देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। जल स्रोतों का संरक्षण, नदियों की स्वच्छता, वृक्षारोपण तथा प्लास्टिक मुक्त वातावरण के लिए प्रत्येक नागरिक को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाकर ही आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान किया जा सकता है।

असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश, बहुविवाह पर प्रतिबंध का प्रावधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। असम सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर एक विधेयक विधानसभा में पेश किया, जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और सह-जीवन (लिव-इन) संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है।

विधेयक में हालांकि कहा गया है कि यह असम में निवास करने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति (एसटी) पर लागू नहीं होगा। इसमें कई दंडात्मक उपायों का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें दो शादियां करने या बहुविवाह के लिए सात साल की कैद और सह-जीवन संबंधों को पंजीकृत नहीं कराने पर तीन महीने की जेल की सजा शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की ओर से विधानसभा में 'असम के लिए समान नागरिक संहिता, 2026 विधेयक' पेश किया। कांग्रेस, रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध किया और इसे पेश करने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की मांग की। असम यूसीसी, भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा रहा एक विवादास्पद मुद्दा है। विधेयक पर बुधवार को सदन में चर्चा होने की संभावना है, जो पांच दिवसीय मौजूदा सत्र का अंतिम दिन है। शर्मा ने विधेयक के 'उद्देश्य और कारणों के कथन' में कहा, ''इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंध से संबंधित कानूनों को एकीकृत और सरल बनाना है।'' मुख्यमंत्री ने बताया कि विधेयक में विवाह के लिए पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। शर्मा ने कहा, ''महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विवाहों को मौजूदा धार्मिक और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न करने की अनुमति देकर असम की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है।'' कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है जो पति-पत्नी के लिए भरण-पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

पश्चिम बंगाल : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के 'जनता दरबार' में भारी भीड़ उमड़ी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपना दूसरा 'जनता दरबार' सोमवार को आयोजित किया, जिसमें बड़ी तादाद में नौकरी के इच्छुक युवा, शिक्षक, पेशेवर और आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखने पहुंचे।

शुभेंदु के आगमन से पहले ही सॉल्ट लेक स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों लोग जमा हो गए और इमारत के आसपास की तंग गलियां प्रतीक्षालय में तब्दील हो गईं। नौकरी के इच्छुक युवाओं के हाथों में फाइल तो बुजुर्ग नागरिकों के हाथों में कागजों के बंडल थे। शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि, नर्सें, पुलिस में नौकरी की इच्छुक महिलाएं और अन्य लोग भी मौजूद थे, जो इस उम्मीद के साथ आए थे कि वर्षों से अनसुनी उनकी फरियाद शायद अब सुनी जाए। सुबह से ही पार्टी कार्यालय के बाहर लंबी कतारें लग गईं। लोग अर्जियां और ज्ञापन लेकर इंतजार करते रहे। शुभेंदु ने नौ मई को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद 'जन-संपर्क' के तहत यह पहल शुरू की थी और 18 मई को पहला 'जनता दरबार' आयोजित किया था। शुभेंदु जब सुबह 10 बजे के आसपास भाजपा कार्यालय पहुंचे, तो वहां 'जय श्री राम', 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' जैसे नारे लगाए गए। कई लोग दूर-दराज के जिलों से सीधे मुख्यमंत्री से मिलने की उम्मीद लेकर आए थे। इस जमावड़े में पश्चिम बंगाल की सामाजिक विविधता साफ दिखी, जहां शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि, 'ग्रुप डी' के अभ्यर्थी, चिकित्सा पेशेवर, अंशकालिक शिक्षक, कथित चुनावी हिंसा के पीड़ित और जन व व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की गुहार लेकर लोग पहुंचे थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कार्यालय के अंदर करीब 100 व्यक्तियों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने बताया कि नौकरी के इच्छुक युवाओं और कर्मचारियों के करीब 15 संगठनों के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपे और भर्ती व सेवा संबंधी चिंताएं उठाईं। सूत्रों के अनुसार, रोजगार से जुड़े मुद्दे सबसे ज्यादा छाए रहे। स्कूल भर्ती रद्द होने से नौकरी गंवा चुके 26,000 उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल ने योग्यता के आधार पर नौकरियां बहाल करने की अपील की। कुछ अन्य लोगों ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्थायी भर्ती फिर से शुरू करने की मांग की और नियुक्ति व सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे उठाए। दिन का सबसे मार्मिक पल तब आया, जब भवानीपुर निवासी प्रबीर मुखोपाध्याय (81) मुख्यमंत्री से मिले।

बंगाल की 'पता लगाओ, हटाओ, निर्वासित करो' नीति ज़मीनी स्तर पर लागू

मालदा/भाषा। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सोमवार को अपनी पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो नीति को लागू किया, जिसके तहत मालदा पहला जिला बन गया, जिसने अवैध विदेशी नागरिकों के लिए एक निरुद्ध केंद्र स्थापित किया है, जहां नौ संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में स्थापित यह निरुद्ध केंद्र, जो वर्तमान में मालदा जिले में इस प्रकार की एकमात्र सुविधा है, अब कार्य कर रही है। रविवार को गाजोल के पांडुआ क्षेत्र से नौ लोगों – जिनमें तीन महिलाएं और छह नाबालिग शामिल हैं – को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां लाया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी निगरानी, 12 पुलिस कर्मियों की तैनाती, नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों और नागरिक स्वयंसेवकों की तैनाती के साथ-साथ भोजन और रखरखाव की व्यवस्था के साथ केंद्र को कई स्तरों की सुरक्षा के दायरे में रखा गया है। मालदा के एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह सुविधा उन विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से रखने के लिए बनाई गई है, जिन्हें अवैध रूप से प्रवेश करने या वैध दस्तावेजों की कमी के आरोप में हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, निरुद्ध केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल, नौ बांग्लादेशी नागरिकों को वहां रखा गया है।

ममता, अभिषेक बनर्जी ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' को दिया समर्थन : डेरेक ओ'ब्रायन

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऑनलाइन मंच 'कॉकरोच जनता पार्टी' को पूर्ण समर्थन दिया है। ओ'ब्रायन ने कहा कि तृणमूल नेतृत्व अब भी अच्छी लड़ाई लड़ने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, ''पूरे हफ्ते ममता और अभिषेक के साथ उद्देश्यपूर्ण बैठकें हुईं। दोनों का ध्यान अच्छी लड़ाई लड़ने पर केंद्रित हैं। दृढ़ संकल्प बना हुआ है। और हां, दोनों ने 'कॉकरोच' के प्रति अपना पूर्ण समर्थन जाहिर किया।''

पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ लगातार रणनीतिक और समीक्षा बैठकें कर रही हैं, ताकि इस राजनीतिक क्षति का आकलन किया जा सके और पार्टी की आगे की दिशा तय की जा सके। अमेरिका बोस्टन में रहने वाले अभिजीत दीपके द्वारा स्थापित 'कॉकरोच जनता पार्टी' 16 मई को शुरू होते ही सोशल मीडिया पर छा गई। इसकी शुरुआत प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की उन टिप्पणियों के कारण हुए विवाद के बाद हुई, जिसे व्यापक रूप से बेरोजगार युवाओं की तुलना ''कॉकरोच'' से करने के रूप में देखा गया।

सपा का 'गुंडाराज' लोग भूले नहीं, 2027 में फिर बनेगी भाजपा की प्रचंड बहुमत सरकार : पाठक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

संभल (उप्र) 25 मई (भाषा)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) के 'गुंडाराज' को लोग अभी तक भूले नहीं हैं। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी।

बिजली व्यवस्था पर अखिलेश यादव के सवालों पर पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा, हम लगातार काम कर रहे हैं। अखिलेश जी से पूछिए कि सपा के शासनकाल में एक हफ्ता दिन में तो एक हफ्ता रात में बिजली आती थी। उन्होंने कहा, 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ एकतरफा भाजपा की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को अभी लोग भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने जिस तरह नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को रोकने का काम किया, देश व प्रदेश की महिलाएं कभी भी सपा और कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। उन्होंने दोहराया, उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा, सम्भल जनपद को विकास में नंबर वन पर लाना है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं जन-जन तक पहुंचें, इस मामले में भी जनपद को अव्वल बनाना है। समीक्षा बैठक में जो भी जरूरतें सामने आई हैं, उन्हें जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि जनता की भावनाओं के अनुरूप आज 'सिंदूर वाटिका' का लोकार्पण किया गया है।

सैनिटरी नैपकिन, अलग शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ें लड़कियां: उच्चतम न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि लड़कियों के सामने सिर्फ़ इसलिए पढ़ाई छोड़ने की स्थिति नहीं आनी चाहिए कि स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन और अलग से शौचालय नहीं हैं। न्यायालय ने केंद्र से इस बारे में उसके निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

उच्चतम न्यायालय का यह बयान तब आया जब केंद्र ने कहा कि 30 जनवरी को दिए उसके फैसले, जिसमें अधिकारियों को लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया था, से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोशिशों में तेजी आई है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा, ''इसे अच्छी तरह लागू करें। यह इस देश की महिलाओं और लड़कियों की भलाई के लिए है। लड़कियों को सिर्फ़ इस वजह से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और घर पर बैठकर कुछ घरेलू काम नहीं करने चाहिए।'' पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से कहा, ''अब, यह आप पर है कि आप इसे अच्छी तरह लागू कराएं और देखें कि जहां तक हो सके, हमारे फ़ैसले के हिसाब से लाभ पहुंचाए जाएं।'' लैंगिक न्याय और शैक्षिक समानता लाने के लिए 30 जनवरी को दिए गए ऐतिहासिक फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लड़कियों को निशुल्क 'ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल' सैनिटरी नैपकिन और स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के लिए लैंगिक आधार पर अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

राहुल गांधी ऐसे बच्चे की तरह जो खिलौना न मिलने पर उसे तोड़ने की फिराक में रहे : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना एक ऐसे बच्चे से की है जो खिलौना न मिलने पर उसे तोड़ने की फिराक में रहता है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस को बिना हिचक यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जनता की उम्मीद और भरोसे का दूसरा नाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं और उनका कोई विकल्प नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा, ''कांग्रेस को बिना किसी हिचक यह स्वीकार करने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि जनता की उम्मीद व भरोसे का दूसरा नाम हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी। उनका कोई विकल्प नहीं है।'' राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि लगातार 12 साल से जनता का विश्वास हासिल करने में नाकाम कांग्रेस नेता विदेशी टूलकिट गैंग के जरिए देश को अराजकता में धकेलने का मंसूबा पाले हैं। उन्होंने आगे लिखा, ''दरअसल, आज राहुल जी की स्थिति उस बच्चे की तरह है, जो खिलौना न मिलने पर उसे तोड़ने की फिराक में रहता है।''

एटा में पानी भरने गई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, दो नामजद आरोपी गिरफ्तार

एटा (उप्र)/भाषा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मारहरा थाना क्षेत्र में कथित तौर पर घर के पास नल से पानी भरने गई 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी का अपहरण कर तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और तीसरे अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। घटना शनिवार रात करीब 11 बजे की है। किशोरी अपने भाई को पानी देने के लिए घर के पास लगे नल पर गई थी। आरोप है कि तभी गांव के ही लवकेश उर्फ लब्बा और निरंजन सिंह एक अज्ञात साथी के साथ वहां पहुंचे। आरोपियों ने किशोरी का मुंह दबाकर उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म किया।

मणिपुर सरकार शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल की मजबूती को प्रतिबद्ध : वाई खेमचंद सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंफाल/भाषा। मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में शांति बनाए रखने के वास्ते पुलिस बल को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से हिंसक आंदोलनों से दूर रहने का आग्रह किया। राज्य में लगभग तीन वर्षों से जातीय हिंसा देखी जा रही है। राज्य पुलिस के लिए 477 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक मजबूत पुलिस बल के बिना मणिपुर में शांति लाना मुश्किल होगा।

सिंह ने कहा, मणिपुर पुलिस के कर्मियों ने राज्य में हिंसा को नियंत्रित करने और रोकने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई और यहां तक कि अपने प्राणों की आहुति भी दी। सेना, असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों ने भी राज्य में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने में समान जिम्मेदारी निभाई।

मई 2023 से लेकर अब तक मैइती और कुकी-ज़ो समूहों के बीच हुई जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी में बम हमले में दो बच्चों की मौत के बाद हुए आंदोलन के दौरान, ऐसे मामले सामने आए जब कुछ युवाओं ने शांतिपूर्ण रैलियां करने और बातचीत करने के बजाय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। मैं सभी से हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने की अपील करता हूं। बाद में 'एक्स' पर एक पोस्ट में सिंह ने कहा, आज प्रथम मणिपुर पुलिस परेड ग्राउंड में गृह मंत्री के. गोविंदास सिंह, विधायकों, गृह आयुक्त, डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में 477 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

नोएडा : झुग्गी बस्ती में भीषण आग, दो दर्जन से अधिक झुग्गियां जलकर राख

नोएडा/भाषा। थाना दनकौर क्षेत्र के खेरली गांव के पास नहर के किनारे बनी झुग्गी बस्ती में सोमवार दोपहर भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आग तेज थी और देखते ही देखते दो दर्जन से अधिक झुग्गियां इसकी चपेट में आ गईं। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि खेरली गांव से गढ़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर नहर के किनारे बनी झुग्गियों में आग लगने की सूचना दोपहर में मिली थी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और आग को फैलने से रोका। हालांकि आग में दो दर्जन से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गईं। उन्होंने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

मणिपुर में छह लोगों की रिहाई की मांग को लेकर नगा समुदाय का प्रदर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंफाल/भाषा। मणिपुर की राजधानी इंफाल में सोमवार को नगा समुदाय के सैंकड़ों सदस्यों ने विरोध रैली निकालकर संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा कथित रूप से बंधक बनाए गए छह लोगों को तत्काल रिहा किए जाने की मांग की। 'नगा पीपुल्स यूनियन इंफाल' की ओर से आयोजित रैली में मेइती समुदाय के कई सदस्य भी शामिल हुए। रैली इंफाल ईस्ट जिले में ट्राइबल मार्केट इलाके से शुरू हुई और मुख्यमंत्री के बंगले की ओर बढ़ी।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के आवास से लगभग 200 मीटर दूर पैलेस गेट के पास सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। हालांकि, उन्होंने बताया कि संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल को आगे जाने और मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह को ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी गई।

ज्ञापन में संगठन ने छह नगा लोगों को बंधक बनाने के आरोपी सशस्त्र कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन ने उपमुख्यमंत्री नेमचा किपजेन को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनके पति उग्रवादी संगठन कुकी नेशनल फ्रंट (प्रेसिडेंशियल) का नेतृत्व करते हैं और अपहरण के लिए जिम्मेदार हैं। ज्ञापन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुकी उग्रवादी समूहों के बीच हुए 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (एसओओ) समझौते को रद्द करने तथा कुकी शरणार्थियों को निर्वासित करने की भी मांग की गई।

प्रदर्शनकारियों ने नेमचा किपजेन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बिना शर्त छह नगाओं को रिहा कराओ और एसओ खत्म करो जैसे नारे लगाए। किपजेन को निशाना बनाते हुए एक पोस्टर पर लिखा था, किसी उग्रवादी की पत्नी उपमुख्यमंत्री कैसे बन सकती है? उल्लेखनीय है कि 13 मई को कांगपोकपी और सेनापति जिलों में तीन गिरजाघर पदाधिकारियों की घात लगाकर हत्या किए जाने के कुछ घंटों बाद, सशस्त्र समूहों ने 38 से अधिक लोगों का अपहरण करके उन्हें बंधक बना लिया था।

बंधक बनाए गए लोगों में 32 (12 नगा महिलाएं और 16 कुकी) को बाद में रिहा कर दिया गया। हालांकि, छह नगा पुरुष अब भी लापता हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इस बीच, कुकी इनपी मणिपुर ने दावा किया कि उसके समुदाय के 14 लोग अब भी नगा समूहों द्वारा बंधक बनाकर रखे गए हैं।

शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री का अहंकार तोड़ देगा 'जेन जेड': कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएसएम) प्रणाली से जुड़ी ''अनियमितताओं'' को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में व्यापक सुधार होना चाहिए।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार सवाल पूछने वाले युवाओं को डराती और बदनाम करती है, लेकिन ये युवा और 'जेन जेड' ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अहंकार तोड़ेंगे। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में ऑन-स्क्रीन मार्किंग मूल्यांकन की एक डिजिटल प्रणाली है। इसमें छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके डिजिटल स्वरूप में कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जाता है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मोदी-प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ़्ते से ओएसएम ग़लत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं।'' उन्होंने कहा, ''17 साल का एक बच्चा, जिसकी कॉपी ग़लत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया। मगर, उसे मदद नहीं, गालियां मिलीं, भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ ने उसे 'राष्ट्र विरोधी' कहा, सोरोस का एजेंट कहा, 'डीप स्टेट' का हिस्सा कहा। जब 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाता है, तो भाजपा उसे देशद्रोही बना देती है।'' राहुल गांधी ने दावा किया कि सच यह है कि

मोदी सरकार युवाओं और 'जेन जेड' से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछने वाले को यह सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। उन्होंने कहा, ''सुन लीजिए, मोदी जी, यही युवा, यही जेन जी आपका अहंकार तोड़ेगा।''

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ''योगी आदित्यनाथ शासित उत्तर प्रदेश में लगातार हुए पेपर लीक और 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान इस मुद्दे को लगातार उठाए जाने के बाद, मोदी सरकार ने फरवरी, 2024 में सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम को संसद से पारित कराया। जहां मोदी सरकार ने इसे ऐतिहासिक कानून बताया, वहीं विपक्षी सांसदों ने उसी समय कहा था कि यह कानून गेस पेपर या अन्य तरीकों से होने वाले पेपर लीक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता।'' उन्होंने कहा, ''आज यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार का जल्दबाजी में लाया गया यह कानून पेपर लीक रोकने के लिए बेहद अपर्याप्त था। भले ही मोदी सरकार कथित तौर पर शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सामने नीट-यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक से इनकार कर रही हो, लेकिन यह साफ है कि एक 'गेस पेपर' सबसे ऊंची बोली लगाने वालों तक पहुंचाया गया था।'' रमेश के अनुसार, पिछले दो वर्षों में लाखों छात्र इसकी कीमत चुका चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ''शिक्षा मंत्री प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए में व्यापक सुधार होना चाहिए और मोदी सरकार को सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तैयार करने, टाइप करने, अनुवाद करने, छापने, पहुंचाने, परीक्षा संचालन और मूल्यांकन तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एक फुलप्रूफ प्रोटोकॉल विकसित करनी चाहिए।''

सुविचार

परछाईं और आईना, कभी झूठ नहीं बोलते, किरदार जैसा होगा, तस्वीर वैसी ही दिखेगी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

डिजिटल अरेस्ट: जिंदगीभर की बचत पर डाका

कर्नाटक राज्य साइबर कमांड ने 'डिजिटल अरेस्ट' एवं 24 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर सराहनीय कार्य किया है। इन लोगों ने खुद को सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताते हुए एक बुजुर्ग महिला से बहुत बड़ी ठगी की थी। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में खास उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। कभी ये मामले बहुत पढ़ने-सुनने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के लिए 'शांति' छा जाती है। फिर ये दोबारा तहलका मचाने लगते हैं। संभवत: एजेंसियों की कार्रवाई से एक बार इनका धंधा मंदा पड़ जाता है। इस दौरान ये उसकी काट ढूंढ़ लेते हैं। उसके बाद दोबारा मैदान में उतरते हैं और लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी गतिविधियों में कई देशों के ठग शामिल हैं। उनके नेटवर्क को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। याद रखिए, हमारे कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इतना खूंखार अपराधी है, जिसकी वजह से सीबीआई, ईडी, रॉ से लेकर तमाम जांच एजेंसियों और पुलिस अधिकारियों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्या उसे सिर्फ डिजिटल अरेस्ट किया जाएगा? ऐसे खतरनाक व्यक्ति की भनक लगते ही उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद अदालत में पेश किया जाता है। अदालत के आदेश के बाद सख्ती से पूछताछ होती है। बड़े-बड़े लोगों को यह सामान्य जानकारी नहीं है, इसलिए जैसे ही उनके पास डिजिटल अरेस्ट संबंधी फोन आता है, वे डर जाते हैं और साइबर ठगों द्वारा दिए गए 'निर्देशों' का पालन करने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। साइबर ठग इस डर का फायदा उठाते हैं। वे लोगों की जिंदगीभर की बचत एक झटके में उड़ा लेते हैं।

नागपुर में एक 72 वर्षीया सेवानिवृत्त नर्स को साइबर अपराधियों ने कई हफ्तों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। आखिर में उनसे 90.65 लाख रुपए ठग लिए। नर्स ने अपने सेवाकाल में हजारों मरीजों की देखभाल की, उन्हें स्वस्थ किया। अब अपनी बचत के सहारे वृद्धावस्था गुजार रही थीं। अगर वे रोजाना 15 मिनट भी अखबार पढ़तीं तो डिजिटल अरेस्ट के जाल में नहीं फंसतीं। वे हफ्तों डिजिटल अरेस्ट रहीं, लेकिन उन्हें एक बार भी साइबर अपराधियों पर शक नहीं हुआ! ये ठग एक खास पैंतरा आजमाते हैं। सबसे पहले सामान्य ढंग से बातचीत करते हैं। जब व्यक्ति को यह 'विश्वास' हो जाता है कि यह वास्तव में कोई सरकारी अधिकारी है, तब एक-एक कर ऐसी बातें सामने लाते हैं, जिससे डर का माहौल बने। वीडियो कॉल पर, उसकी बात पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति से कराई जाती है, जो ठगों का साथी होता है। चूंकि हमारे देश में पुलिस को देखकर शरीफ लोग वैसे ही डर जाते हैं, इसलिए सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। वे यही सोचते हैं कि किसी तरह इस आफत से बाहर निकलें। जब साइबर ठग देख लेते हैं कि यह व्यक्ति पूरी तरह डरा हुआ है, तब वे एक और दांव चलते हैं। वे कहते हैं, 'आप तो अच्छे घर के लगते हैं ... भले आदमी मालूम होते हैं ... हम जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं ... हमें भी पता है कि आप बेकसूर हैं...।' ये शब्द सुनते ही उस व्यक्ति को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसे लगता है कि अब यह मुसीबत दूर हो सकती है, क्योंकि 'अधिकारी' को मेरी बातों पर विश्वास हो रहा है। उसके बाद वह ठगों के बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर कर देता है। जब तक उसे हकीकत मालूम होती है, साइबर ठग किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। अगले शिकार आप न हों, इसके लिए खुद जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। अखबार के माध्यम से रोजाना अपनी जानकारी में किया गया छोटा-सा निवेश आपकी जिंदगीभर की बचत को सुरक्षित रख सकता है।

ट्वीटर टॉक

अब बिचौलियों का खेल नहीं, सीधे अकाउंट में पैसा! भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार का उ्इढ स्ट्राइक! टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी से, अब सरकारी स्कीम का पैसा सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है।

–अर्जुनरम मेघवाल

आज भरतपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ मीटिंग में जिले में चल रहे अलग-अलग डेवलपमेंट के कामों और पब्लिक वेलफेयर स्कीमों का डिटेल में रिव्यू किया गया।अधिकारियों को कहा गया कि सभी प्रोजेक्ट तय समय में और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरे हों।

–भजनलाल शर्मा

मोदी-शाह की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया है। दशकों में पहली बार, उइड्ए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इतने गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थीऔर अब एक हफ़्ते से, गलत मार्किंग और मूल्यांकन में गड़बड़ियों की शिकायतें अनसुनी हैं।

–राहुल गांधी

प्रेरक प्रसंग

समता की तार्किकता

संतराम गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर में बी.ए. के छात्र थे। एक दिन वे भोजन कक्ष में भोजन करने बैठे। उसी दौरान वे जान-बूझकर अपने एक सहपाठी से छू गए, जो पास में बैठकर भोजन कर रहा था। बस फिर क्या था, वह छात्र आगबबूला हो उठा। अपनी थाली वहीं छोड़ते हुए बोला, 'संतू मुझसे छू गया है। मेरी थाली का खर्च इसके नाम लिख देना।' संतराम ने तुरंत उसकी बांह पकड़ ली और उसे वहीं बैठाकर बोले, 'जरा अपनी यह क्रिस्टल टोपी उतारकर उल्टी रखो।' उसने टोपी उतारी। संतराम ने पूछा, 'इसके भीतर लगी पट्टी किस चीज़ की है?' वह बोला, 'खाल की।' संतराम मुस्कुराकर बोले, 'तो क्या मैं इस टोपी में लगी मरी हुई खाल से भी अधिक अछूत हो गया हूं, जिसके कारण तुम थाली छोड़कर भाग रहे हो? इस टोपी को तो तुम सम्मान से सिर पर लगाए घूमते हो। जाओ, अब थाली छोड़ दो और भूखे रहो। मैं इस थाली का खर्च हरगिज़ नहीं दूंगा। भोजन में छूत-अछूत नहीं, बल्कि सात्विकता देखी जाती है। यदि भोजन सात्विक होगा, तो विचार भी सात्विक होंगे।' संतराम की बात सुनकर वह छात्र शांत हो गया और पुनः भोजन करने बैठ गया।

सामयिक

देश व समाज हित में है डीजल व पेट्रोल की बचत की मांग!

दीपक कुमार त्यागी

वैसे तो देशभर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही यह मुहिम धरातल पर धीरे-धीरे रंग लाती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद से ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के आम कार्यकर्ताओं तक ने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर इस मुहिम में शामिल होकर के इसको एक आंदोलन का रूप देने का कार्य किया। जिसके बाद से ही देश भर में ज्यूडिशियरी, शीर्ष नौकरशाह, कर्मचारी व आम जनमानस तक भी मोदी की इस मुहिम में अब बड़े पैमाने पर शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। शासन-प्रशासन के शीर्ष स्तर पर काबिज बैठे हुए ताकतवर लोगों में देश भर में वाहनों के लंबे-चौड़े काफिले का त्याग करने की फिलहाल तो एक होड़ लगी हुई है। हालांकि उन लोगों का यह कदम वास्तव में दिल से खर्चों में कटौती करते हुए जीवन में सादगी अपनाने की धरातल पर एक स्थाई पहल है या सिर्फ मीडिया व सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपनी कुछ पोस्ट डालकर के वाहवाही लूटने की एक नौटंकी मात्र है, यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम युद्ध के माहौल के चलते जब पूरी दुनिया ऊर्जा व आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस अपील पर भारत में धरातल पर अमल शुरू होना देश व समाज हित के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है।

> विचारणीय तथ्य यह भी है कि आजकल देश में जिस तरह से सरकारी या गैरसरकारी लोगों के मन में अपने आपको एक बड़ा वीवीआईपी दिखाने की चाह रहती है, वह चाहते देश व समाज हित में ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों को वीवीआईपी दिखाने की चाहत में सिस्टम का बड़ा तामझाम, लग्जरी मंहगी गाड़ियों के लंबे-चौड़े काफिले, चार्टर प्लेन आदि दिखावे पर जनता के द्वारा देश के विकास के लिए दिये गये टैक्स की काफी धनराशि का दुरुपयोग होता है, जिसको तत्काल रोका जाना चाहिए।

लेकिन विचारणीय तथ्य यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह मुहिम कुछ समय की ना होकर के देश व समाज हित में धरातल पर दीर्घकालीन स्थाई रूप ले पायेगी, हालांकि यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह से युद्धों के चलते बेहद ही तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, उस माहौल का स्पष्ट रूप से संदेश है कि अब वह दौर आ गया है जब देश व समाज के हित में जनता के टैक्स के पैसे के दम पर राजा-महाराजाओं की तरह पूरी शानो-शौकत व ठाट-बाट से जीवन व्यतीत कर रहे शासन-प्रशासन के लोग सादगी से जीवनयापन करने की आम जनमानस के सामने नज़ीर पेश करते हुए लोगों को भी सादा जीवन उच्च विचार के लिए प्रेरित करें। वैसे भी देखा जाए तो अब देश व दुनिया में वह दौर शुरू हो गया है, जब देश व समाज के हित की बातें सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफ्तरों में बैठकर के आम जनमानस पर अपने विचार या नियम-कानून बना कर के थोप देने मात्र से ही पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि उस पर अमल करवाने के लिए शासन-प्रशासन में बैठे हुए ताकतवर लोगों को भी स्वयं अनुशासित होकर के जीवन पथ पर सादगी व जवाबदेही को अपनाकर उदाहरण पेश करना चाहिए, तब ही आम जनमानस भी उन लोगों की देखा-देखी उस पर अमल करने का कार्य करेगा। लेकिन आज के वीवीआईपी बनकर के दिखाने वाले दौर में जिस तरह के राजसी ठाट-बाट के साथ कुछ राजनेताओं व शासन-प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग सरकारी व निजी दौरों के दौरान अनाप-शनाप खर्चा करते हैं, क्या ऐसे लोग के द्वारा देश व समाज हित में उन सभी अनावश्यक खर्चों में स्वयं ही कटौती करने की पहल करके जनता के सामने एक बड़ी मिसाल कायम नहीं करनी चाहिए।

विचारणीय तथ्य यह भी है कि आजकल देश में जिस तरह से सरकारी या गैरसरकारी लोगों के मन में अपने आपको एक बड़ा वीवीआईपी दिखाने की चाह रहती है, वह चाहते देश व समाज हित में ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों को वीवीआईपी दिखाने की चाहत में सिस्टम का बड़ा तामझाम, लग्जरी मंहगी गाड़ियों के लंबे-चौड़े काफिले, चार्टर प्लेन आदि दिखावे पर जनता के द्वारा देश के विकास के लिए दिये गये टैक्स की काफी धनराशि का दुरुपयोग होता है, जिसको तत्काल रोका जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों के द्वारा अपना भौकाल बनाने के लिए व दिखावे के लिए ली गयी अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव में होने वाले अतिरिक्त खर्चों को भी अब बिल्कुल सीमित करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से चंद लोग सिस्टम में बैठे कुछ ताकतवर लोगों की कृपा से सरकारी अमले की आड़ में जनता के टैक्स के पैसों पर मौज मस्ती करते हुए जनता का ही आये दिन उत्पीड़न करते हैं, यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों से सांठ-गांठ करके हमारे प्यारे देश में धनपशु, दलाल व अपराधी तक भी सरकारी सुरक्षा व सुविधाओं के भौकाल का आनंद लें रहे हैं, जो नियम कायदे व कानून पसंद देशभक्त देशवासियों के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। देश व समाज हित में जनता के द्वारा टैक्स के रूप में दी गई धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं, महिलाओं, किसानों और उधोग-धंधों आदि के साथ-साथ देश के सर्वांगीण विकास पर खर्च हो। देश की जनता के टैक्स का धन देश के विकास और आम जनमानस की भलाई में लगे, न कि वीवीआईपी बनने की चाहत के बेफिजूल के खर्चो और शानो-शौकत में लगे। इसलिए अब देश व समाज हित में वह समय आ गया है जब शासन व प्रशासन में बैठे लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोना ना खरीदने व डीजल और पेट्रोल बचाने की पहल को दो कदम आगे बढ़ाते हुए स्वयं ही अनुशासित होकर के जीवन पथ पर सरलता व सादगी अपनाकर देश व समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करेंगें और भारत का नव निर्माण करते हुए देश को विश्व गुरु बनायेंगे।

(साभार : प्रभासाक्षी)

नजरिया

यह कैसा समाज है, जिसमें अदालतें समझाएं रिश्तों का धर्म

ललित गर्ग

मो. 9811051133

> आज आवश्यकता है कि विकसित भारत 2047 की अवधारणा में वृद्ध सम्मान को भी एक महत्वपूर्ण सूचक बनाया जाए। जिस देश में बुजुर्ग सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट होंगे, वही वास्तव में विकसित कहा जा सकेगा। हमें ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिनमें वृद्धजन कल्याण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग को प्राथमिकता मिले। साथ ही परिवारों को यह समझना होगा कि माता-पिता केवल जिम्मेदारी नहीं, हमारी जड़ें हैं। जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाएँ, उसकी शाखाएँ अधिक समय तक हरी नहीं रह सकतीं। माता-पिता की उपेक्षा केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरी पीढ़ी की नैतिक पराजय है।

किसी भी सभ्यता की वास्तविक पहचान उसकी ऊँची इमारतों, चमकती सड़कों, आर्थिक प्रगति या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों, माता-पिता और निर्बल वर्ग के प्रति कितना संवेदनशील है। लेकिन आज का सबसे पीड़ादायक प्रश्न यही है कि जिस भारत ने मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः का उद्घोष किया, जिस धरती से वसुधैव कुटुम्बकम् का विचार पूरी दुनिया में पहुँचा, उसी भूमि पर आज माता-पिता को अपने ही घर में सम्मान और आश्रय पाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में देश की अदालतों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है, जहाँ वृद्ध माता-पिता को अपने ही बच्चों से संरक्षण, भरण-पोषण, रहने की व्यवस्था और संपत्ति पर अधिकार के लिए न्यायिक हस्तक्षेप लेना पड़ा। कहीं बेटे को अदालत यह निर्देश दे रही है कि वह अपनी वृद्ध मां को घर में एक कमरा, अलग स्नानघर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए, तो कहीं दुर्व्यवहार करने वाली संतान को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल करने के आदेश दिए जा रहे हैं। यह केवल कानूनी घटनाएँ नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और नैतिक पतन की वे चेतावनियाँ हैं जो भविष्य के भारत की तस्वीर पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रही हैं।

वास्तव में यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि जिस मां ने नौ महीने गर्भ में रखकर संतान को जीवन दिया, जिसने अपना रक्त, ममता और त्याग देकर उसे पाला, उसी मां को अपने ही घर में रहने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़े। जिस पिता ने अपने पसीने और परिश्रम से घर बनाया, बच्चों का भविष्य संवारा, वृद्धावस्था में उसी घर में उसके अधिकार के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े, यह स्थिति केवल व्यक्तिगत कृतघ्नता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं के क्षरण का प्रमाण है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति, स्मार्ट शहर, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं। लेकिन यदि घर के किसी कोने में बैठे वृद्ध माता-पिता अकेलेपन, उपेक्षा और अपमान का जीवन जी रहे हों, तो क्या यह विकास पूर्ण माना जा सकता है? यदि हमारे बुजुर्ग अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर और उपेक्षित हो जाएँ, तो हमारी सारी उपलब्धियाँ खोखली प्रतीत होती हैं।

आज की सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक निर्धनता की है। नई पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। भौतिक उपलब्धियाँ, कैरियर, उपभोगवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणाएँ जीवन के केंद्र में आ गई हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों की ऊष्मा कम हो रही है और संवाद का स्थान डिजिटल माध्यम ले रहे हैं। परिणामतः बुजुर्गों का जीवन अकेलेपन, अवसाद और असुरक्षा का पर्याय बनता जा रहा है। यह सच है कि महानगरीय जीवन की अपनी कठिनाइयाँ हैं। रोजगार, समयाभाव, आर्थिक दबाव और बदलती जीवनशैली ने नई पीढ़ी की चुनौतियाँ बढ़ाई हैं। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद माता-पिता के प्रति दायित्व समाप्त नहीं हो सकते। भारतीय संस्कृति में माता-पिता की सेवा केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन-मूल्य रही है। श्रवण कुमार का आदर्श केवल कथा नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का हिस्सा है।

दुर्भाग्य यह है कि आज संपत्ति और स्वार्थ ने अनेक संबंधों को प्रभावित किया है। अखबारों में आए दिन ऐसे समाचार दिखाई देते हैं जिनमें संपत्ति के लिए माता-पिता को प्रताड़ित किया जाता है, घर से निकाला जाता है, मानसिक यातना दी जाती है या उनकी उपेक्षा की जाती है। अनेक वृद्धाश्रम ऐसे माता-पिता से भरे पड़े हैं जिनकी सबसे बड़ी गलती केवल यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर दी। यदि यह प्रवृत्ति यूँ ही बढ़ती रही तो भारत भी उस दिशा में बढ़ सकता है जहाँ पश्चिमी देशों की तरह माता-पिता और संतान के संबंध केवल कानूनी और औपचारिक होकर रह जाएँ।

पश्चिमी समाज में अनेक माता-पिता प्रारंभ से ही बच्चों को आत्मनिर्भर बना देते हैं क्योंकि वे भविष्य में उनसे देखभाल की अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन भारतीय समाज का आधार इससे भिन्न रहा है। यहाँ परिवार केवल जैविक इकाई नहीं, बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था रहा है।

यह भी स्मरणीय है कि देश में वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 जैसे कानून बनाए गए हैं ताकि वृद्ध माता-पिता के अधिकारों की रक्षा हो सके। न्यायालयों ने अनेक अवसरों पर माता-पिता के संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित रखा है और दुर्व्यवहार करने वाली संतानों के विरुद्ध कठोर टिप्पणियाँ भी की हैं। लेकिन कानून केवल सुरक्षा दे सकता है, संवेदना नहीं। अदालतें कमरे दिला सकती हैं, सम्मान नहीं, भरण-पोषण का आदेश दे सकती हैं, लेकिन ममता और अपनत्व नहीं लौटा सकतीं। यही कारण है कि समाधान केवल कानूनी नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक होना चाहिए। परिवारों में संस्कारों की पुनर्स्थापना आवश्यक है। बच्चों को केवल उच्च शिक्षा और आधुनिक सुविधाएँ देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें मानवीय मूल्य भी देना होंगे। विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को परिवार, सेवा, कृतज्ञता और बुजुर्ग सम्मान जैसे विषयों पर गंभीर पहल करनी चाहिए।

आज आवश्यकता है कि विकसित भारत 2047 की अवधारणा में वृद्ध सम्मान को भी एक महत्वपूर्ण सूचक बनाया जाए। जिस देश में बुजुर्ग सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट होंगे, वही वास्तव में विकसित कहा जा सकेगा। हमें ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिनमें वृद्धजन कल्याण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग को प्राथमिकता मिले। साथ ही परिवारों को यह समझना होगा कि माता-पिता केवल जिम्मेदारी नहीं, हमारी जड़ें हैं।

जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाएँ, उसकी शाखाएँ अधिक समय तक हरी नहीं रह सकतीं। माता-पिता की उपेक्षा केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरी पीढ़ी की नैतिक पराजय है। यह भी विचारणीय है कि जो संतान आज अपने माता-पिता के साथ व्यवहार कर रही है, वही व्यवहार भविष्य में उसके हिस्से भी आ सकता है। बच्चे केवल उपदेश से नहीं, व्यवहार से सीखते हैं। यदि वे अपने माता-पिता को बुजुर्गों की उपेक्षा करते देखेंगे तो वही संस्कार आगे बढ़ेंगे।

आज आवश्यकता अदालतों के आदेशों से अधिक अंतःकरण के जागरण की है। रिश्तों की मर्यादाएँ, गरिमा और दायित्व यदि न्यायालयों को समझाने पड़ें तो यह केवल कानूनी संकट नहीं, बल्कि सभ्यता का संकट है। यह समय आत्ममंथन का है कि क्या हम तकनीकी रूप से आधुनिक होते-होते मानवीय रूप से निर्धन होते जा रहे हैं? भारत की पहचान उसकी संवेदनशीलता रही है। यदि हम इस संवेदनशीलता को बचा सके, तभी विकसित भारत का स्वप्न सार्थक होगा।

अन्यथा ऊँची उपलब्धियों और भव्य योजनाओं के बीच भी हमारे घरों के किसी कोने में बैठा एक उपेक्षित वृद्ध हमारी समस्त प्रगति पर मौन प्रश्नचिह्न बनकर खड़ा रहेगा। अंततः याद रखना होगा- विरासत संपत्ति नहीं, संस्कार होते हैं, विकास इमारतों से नहीं, रिश्तों से मापा जाता है और वह समाज कभी महान नहीं कहलाता जहाँ माता-पिता को अपने अधिकार के लिए अदालतों में खड़ा होना पड़े।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

धार में 'मां सरस्वती लोक' और राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना होगी : मोहन यादव

धार/भाषा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को भोजशाला परिसर में पूजा-अर्चना करने के बाद कहा कि धार में 'मां सरस्वती लोक' और 'राजा भोज शोध संस्थान' की स्थापना की जाएगी।

हाल ही में उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित एक हिंदू मंदिर घोषित किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धार में 'मां सरस्वती लोक' और 'राजा भोज शोध संस्थान' स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने हालांकि इसके स्वरूप का विस्तृत विवरण नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि सरस्वती लोक ज्ञान की देवी को समर्पित एक आध्यात्मिक गलियारा होगा। उन्होंने कहा, ''पिछले 750 वर्षों में पहली बार भोजशाला में देवी वाग्देवी की विधिवत पूजा-अर्चना की गई और यह पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने यहां अनुष्ठान किया है।''

यादव ने धार के विकास का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार शहर के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

अधिकारियों के अनुसार, भोजशाला परिसर में प्रवेश के बाद मुख्यमंत्री ने देवी वाग्देवी के चित्र के समक्ष ध्यान लगाया और आरती में भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धार राजा भोज की नगरी है, जिन्हें मालवा क्षेत्र से जुड़े सम्राट विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के समकक्ष माना जाता है। उन्होंने कहा, ''राजा भोज ने अनेक ग्रंथों की रचना की और प्राचीन महत्व की कई इमारतों का निर्माण कराया। उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनवाया। उन्होंने नदी के मुख्य प्रवाह को रोकने के बजाय भोपाल तालाब का निर्माण कराया। उनकी तकनीक से विद्वान भी आश्चर्यचकित हैं।'' यादव ने कहा कि राजा भोज ने एक सम्मेलन आयोजित कर उसमें भाग लेने वाले कवियों को सोने की ईंट पुरस्कार स्वरूप दी थीं, जो हमारे गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। भोजशाला मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब धार एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने इस फैसले के लिए धार के लोगों को बधाई दी।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने अपने फैसले में भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर बताया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सात अप्रैल 2003 के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को प्रत्येक शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी।मुख्यमंत्री ने कहा, ''यह निर्णय 750 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। अदालत ने इस मामले में सही निर्णय दिया है। आने वाले समय में हमें धार जिले को और आगे बढ़ाने का संकल्प लेना होगा।'' उन्होंने कहा, ''हमने मां सरस्वती के दर्शन कर धार के विकास का संकल्प लिया है। हम इसे मां सरस्वती की भूमि बनाएंगे। यहां लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह पर्यटन और साहित्य का केंद्र बनेगा।''

राजा भोज के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भी जल संरक्षण से जुड़े अनेक कार्य किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर 88 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 12 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया।

बचाव

ऋषिकेश में सोमवार को भीषण गर्मी में खुद को चिलचिलाती धूप और लू से बचाने के लिए कपड़े से ढकी हुई महिलाएं।

भारत ने श्रीलंका में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद के लिए 134 पुलिस वाहन सौंपे

कोलंबो/भाषा। भारत ने सोमवार को कोलंबो में राष्ट्रपति भवन परिसर में आयोजित समारोह में श्रीलंका को 134 पुलिस वाहन सौंपे, जिसे दोनों देशों के बीच ''बहुआयामी विकास साझेदारी'' में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

इस सौदे से जुड़े समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दिसंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की नई दिल्ली यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए थे।

भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ''राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके की गरिमामयी उपस्थिति में श्रीलंका पुलिस को 30 करोड़ श्रीलंकाई रुपए से खरीदे गए 134 वाहन सौंपे गए।'' उन्होंने बताया कि श्रीलंका पुलिस के अनुरोध पर की गई यह पहल सड़क सुरक्षा, नागरिकों को समय पर मदद पहुंचाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगी।

ईंधन उपकर पर विचार किया जा रहा है : सतीशन

तिरुवनंतपुरम/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर को वापस लेने के बारे में सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि ईंधन की कीमतें अब भी काफी अधिक हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मुद्दे की अभी विस्तृत समीक्षा की जा रही है।

सतीशन ने कहा, फिलहाल हम इस मामले पर गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम किसी अंतिम निर्णय की स्थिति में नहीं हैं। स्थिति हर दिन बदल रही है।

केरल में वाम दलों की सरकार के दौरान बढ़ती वित्तीय जरूरतों के बीच अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रयास के तहत पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाया गया था। उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे सतीशन ने इसके खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी और कहा था कि इससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है तथा ईंधन की कीमतों का दबाव बढ़ता है।

सतीशन ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव और आम लोगों पर पड़ने वाले बोझ दोनों का आकलन कर रही है।

केरल के मुख्यमंत्री सतीशन का गुरुवायूर मंदिर जाना उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन : भाजपा

त्रिशूर/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन के प्रसिद्ध गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर की यात्रा करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि रविवार को मंदिर में 'वीआईपी दर्शन' को लेकर केरल उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया और आम श्रद्धालुओं को असुविधा हुई।

सतीशन ने रविवार को गुरुवायूर मंदिर में पूजा-अर्चना की और पारंपरिक 'तुलाभारम' अनुष्ठान भी किया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता बी गोपालकृष्णन ने गुरुवायूर देवस्वोम प्रशासन को शिकायत देकर आरोप लगाया कि रविवार सुबह प्रतिबंधित समय के दौरान मुख्यमंत्री और उनके साथ आए नेताओं को विशेष वीआईपी दर्शन की सुविधा दी गई। उन्होंने 24 मई को फेसबुक पर एक पोस्ट में दावा किया कि उच्च न्यायालय ने रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है। साथ ही, मंदिर परिसर और मेलपथुर सभागार के आसपास वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर भी प्रतिबंध है।

गोपालकृष्णन ने आरोप लगाया कि सतीशन और उनके सहयोगियों को सुबह करीब साढ़े सात बजे से साढ़े नौ बजे के बीच 4,500 रुपए की अनिवार्य 'श्रीकोविल नेयविलक्कु' रसीद के बिना वीआईपी दर्शन कराया गया। नियमों के अनुसार अवकाश के दिनों में विशेष दर्शन के लिए यह रसीद लेना आवश्यक है।

मंदिर के नियमों के मुताबिक 'नेयविलक्कु' रसीद लेने वाले श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन की अनुमति मिलती है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद हिबी ईडन सहित कई वीआईपी लोगों ने मना करने के बावजूद मंदिर परिसर के आसपास वीडियो बनाये। उन्होंने शिकायत में कहा, जो लोग कानून की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही उसका उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि देवस्वोम प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो कानूनी कदम उठाए जाएंगे।हालांकि, मंदिर का प्रबंधन करने वाले गुरुवायूर देवस्वोम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का दर्शन नियमों के अनुसार कराया गया था। देवस्वोम ने सोमवार को फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट किया कि रविवार अवकाश का दिन होने के कारण सतीशन ने 4,500 रुपए की 'श्रीकोविल नेयविलक्कु' रसीद लेकर दर्शन किया था।

हालांकि, देवस्वोम की फेसबुक पोस्ट में विवाद का कोई उल्लेख नहीं किया गया। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवायूर देवस्वोम के अध्यक्ष ए वी गोपीनाथ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में अवकाश के दिनों में वीआईपी दर्शन पर रोक है, लेकिन प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री और उनके दल द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किये जाने का मामला नजर नहीं आता।

परिणीति चोपड़ा ने शेयर किया देसी और हेल्दी लिट्टी चोखा

मुंबई/एजेन्सी

आजकल फिल्मी सितारे सिर्फ अपने काम को लेकर ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी और रोजमर्रा की आदतों को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं। इसी बीच अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने एक खास पोस्ट से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने अपने घर के बने हेल्दी खाने की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें भारतीय स्वाद और सेहत दोनों की झलक दिखाई दी। परिणीति चोपड़ा ने सोमवार सुबह अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लिट्टी चोखा की प्लेट नजर आ रही है। प्लेट में लिट्टी रखी हुई है और साथ में एक कटोरी में आलू और बैंगन से बना चोखा भी रखा दिखाई दे रहा है। इस पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींचा। इस पोस्ट के साथ परिणीति ने कैप्शन में लिखा, यह

लिट्टी चोखा घर पर बनाया गया है और इसे हेल्दी बनाने के लिए खास ध्यान रखा गया है। लिट्टी ज्वार के आटे से तैयार की गई है, जिसमें सत्तू की भरपूर स्टफिंग डाली गई है। साइड डिश के रूप में आलू और बैंगन का चोखा बनाया गया है।

बता दें कि मां बनने के बाद से परिणीति चोपड़ा अपनी सेहत और खानपान पर ज्यादा ध्यान देने लगी हैं। इस पोस्ट के अलावा, परिणीति ने एक अन्य पोस्ट भी साझा किया, जिसमें वह ब्राउन कलर की आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है। वह एक मेकअप रूम में खड़ी हैं, बैकग्राउंड में मिरर और कुछ कपड़े नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में परिणीति ने लिखा, पीछे मेस, आगे ड्रेस... इस कैप्शन का कोई मतलब है??? निजी जीवन की बात करें तो परिणीति चोपड़ा की शादी नेता राघव चड्ढा से हुई है। दोनों ने सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर में एक निजी, लेकिन बेहद भव्य समारोह में शादी की थी। इस शादी में केवल करीबी परिवार के सदस्य और चुनिंदा लोग शामिल हुए थे।

जनता दरबार

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भाजपा कार्यालय में सोमवार को आयोजित 'जनता दरबार' कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मिलने के लिए एकत्र हुए लोग।

सलमान खान का इंस्टाग्राम प्रोफाइल कुछ समय के लिए हुआ बंद

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। दरअसल, सोमवार को अचानक सलमान खान का इंस्टाग्राम प्रोफाइल कुछ समय के लिए गायब हो गया, जिसके बाद फैंस के बीच हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर लोग लगातार यह जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर अभिनेता का अकाउंट अचानक डीएक्टिवेट कैसे हो गया। जब लोग सलमान खान की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलने की कोशिश कर रहे थे, तब स्क्रीन पर 'यह पेज उपलब्ध नहीं है' जैसा मैसेज दिखाई दे रहा था। इससे कई लोगों को लगा कि शायद अभिनेता ने अपना अकाउंट बंद कर दिया है। हालांकि, थोड़ी देर बाद उनकी प्रोफाइल पहले की तरह दिखाई देने लगी।

अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह तकनीकी खराबी थी, अकाउंट को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था या फिर किसी ने हैक करने की कोशिश की थी। इस मामले में सलमान खान या उनकी टीम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन, सोशल मीडिया पर फैंस और यूजर्स कई तरह की बातें कर रहे हैं।

बता दें कि सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके 72 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उनकी हर पोस्ट और अपडेट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सलमान अक्सर अपने काम, फिल्मों, फिटनेस और निजी जिंदगी से जुड़ी बातें सोशल मीडिया के जरिए साझा करते रहते हैं।

यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही सलमान खान ने मीडिया और फोटोग्राफर्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सलमान खान हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें देखकर पैपराजी ने उनकी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' चिल्लाना शुरू कर दिया। इस शोर से सलमान भड़क गए और नाराजगी जताई। उन्होंने पैपराजी को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खरी-खोटी भी सुनाई थी।

अभिनंदन

कोलकाता में सोमवार को भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान भाजपा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश पचिसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश अग्रवाल और अन्य भी उपस्थित रहे।

वामीका गब्बी ने एक विशेष सवारी के साथ 'भूल चूक माफ' के 1 साल पूरे होने का मनाया जश्न

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री वामिका गब्बी ने अपनी फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'भूल चूक माफ' की रिलीज के एक साल पूरे होने का जश्न ई-रिक्शा की विशेष सवारी के साथ मनाया। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वामिका ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो क्लिप अपलोड की, जिसमें वह दुल्हन के लिबास में सजी हुई एक कार में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं और रास्ते में सभी को बता रही हैं कि आज उनकी शादी का दिन है।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक साल पहले आप सब ने हमारी शादी में शामिल होके हमको इतना प्यार दिया! उसके लिए शुक्रिया! कुछ भूल चूक होगी हो तो माफ कर दीजिएगा।करण शर्मा के निर्देशन में बनी भूल चूक माफ को दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।नाटक के प्राथमिक कलाकारों में वामीका, राजकुमार राव और सीमा पाहवा शामिल हैं, जबकि संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, रघुबीर यादव, इश्तियाक खान, पूर्णिमा शर्मा, अनुभा फतेहपुरिया और विनीत कुमार सहायक कलाकार के रूप में हैं।भूल चूक माफ 23 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं।

यह प्रोजेक्ट बनारस के एक छोटे शहर के लड़के रंजन (राजकुमार द्वारा अभिनीत) की कहानी बताता है, जिसे अपनी प्रेमिका तितली (वामिका द्वारा अभिनीत) से शादी करने के लिए सरकारी नौकरी मिल जाती है। हालांकि, वह भगवान शिव से किया एक महत्वपूर्ण वचन भूल जाता है, जिसके कारण वह समय के एक चक्र में फंस जाता है।

अब तकनीकी टीम की बात करें तो, इस ड्रामा की सिनेमैटोग्राफी सुदीप चटर्जी ने की है, जबकि संपादन

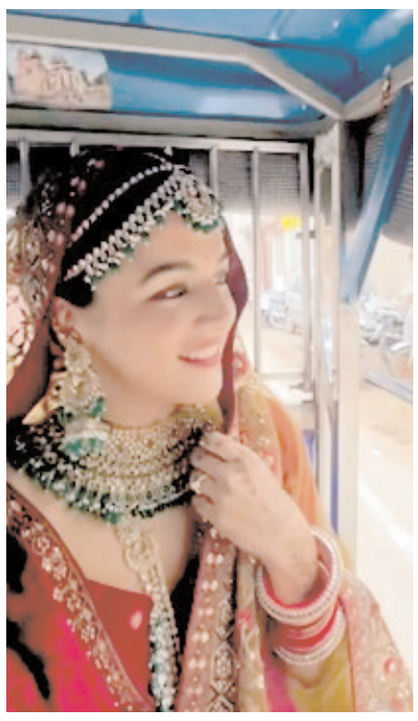

का जिम्मा मनीष प्रधान के पास है।इसके बाद, वामिका पहली बार करण जौहर की फिल्म कुछ्छ की कुंडली में लोकप्रिय यूट्यूबर भुवन बाम के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। इस प्रोजेक्ट का निर्देशन शरण शर्मा कर रहे हैं, जो गुंजन सक्सेनाः द कारगिल गर्ल और मिस्टर एंड मिसेज माही जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

मौनी रॉय ने अपने अंदाज में कान्स को कहा अलविदा

मुंबई/एजेन्सी

टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बना चुकी मौनी रॉय इन दिनों कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। हर बार की तरह इस बार भी मौनी ने अपने फैशन और स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचा। अब कान्स में अपने आखिरी दिन मौनी रॉय ने एक बार फिर बेहद खूबसूरत तस्वीरें साझा कर फ्रेंच रिवेरा को अलविदा कहा है। उनके इस नए लुक के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी फिर चर्चा में आ गई है। मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में वह समुद्र के सामने बनी एक बालकनी में खड़ी नजर आ रही हैं। उन्होंने वाइट और ब्लू कलर की प्रिंटेड लॉन्ग ड्रेस पहनी है। इस ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत लग रही है। तस्वीरों में वह अलग-अलग अंदाज में पोज देती दिखाई दे रही हैं। कहीं वह मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रही हैं तो कहीं समुद्र की ओर देखते हुए तस्वीरें खिंचवा रही हैं। अपने पूरे लुक को मौनी ने बेहद सिंपल, लेकिन स्टाइलिश रखा। उन्होंने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। इसके साथ उन्होंने ज्यादा गहने नहीं पहने, बल्कि सिर्फ एक बड़ा कड़ा हाथ में पहना हुआ था। लाइट मेकअप से उनका चेहरा निखर रहा था। फैंस को उनका यह क्लासी अंदाज काफी पसंद आया।

इन तस्वीरों के साथ मौनी रॉय ने कैप्शन में लिखा, मैं अगले साल तक के लिए फ्रेंच रिवेरा और कान्स को अलविदा कह रही हूं। पिछले कुछ दिनों से मौनी लगातार कान्स से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो साझा कर रही थीं। हर लुक में

उनका अलग अंदाज देखने को मिला। सोशल मीडिया पर उनके फैशन की खूब चर्चा हुई। हालांकि, कान्स में उनके फैशन के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी लगातार खबरों में बनी रही। हाल ही में मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने अलग होने की जानकारी दी थी।इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स में एलिमनी, आपसी विवाद और किसी तीसरे व्यक्ति के शामिल होने जैसी बातें कही जाने लगीं।इन अफवाहों के बढ़ने के बाद सूरज नांबियार ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा कि उनके अलग होने को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह झूठी और गलत हैं। उनके और मौनी के बीच किसी तरह का पैसों का विवाद नहीं है। उनके रिश्ते के टूटने के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं है। हमने आपसी समझदारी के साथ अलग होने का फैसला लिया है।

महेन्द्र मांडोत बने तेरापंथ सभा चेन्नई के नए अध्यक्ष

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तेरापंथी सभा चेन्नई के अध्यक्ष अशोक खतंग की अध्यक्षता में तेरापंथ भवन में वार्षिक साधारण सभा का आयोजन रविवार को हुआ। श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन श्री तनसुख नाहर ने किया। अशोक खतंग ने सभी का स्वागत करते हुए सभा की गतिविधियों का वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सभा के अंतर्गत विभिन्न विभागीय प्रभारियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री प्रतिवेदन व कोषाध्यक्ष रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। सभा का संचालन मंत्री गजेंद्र खाँटेड ने किया।

चुनावी प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए चुनाव अधिकारी अशोक बोहरा व सहचुनाव अधिकारी दिनेश भंसाली ने अध्यक्षीय पद हेतु महेंद्र मांडोत व अनिल सेठिया के नामांकन पत्रों की जानकारी दी तथा मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराई। मतगणना के आधार पर चुनाव अधिकारियों ने वर्ष 2026-28 के लिए महेन्द्र मांडोत को अध्यक्ष पद पर चुने जाने की घोषणा की। तेरापंथ धर्मसंघ की सभी संस्थाओं व ट्रस्ट बोर्ड आदि के प्रतिनिधियों, अध्यक्षीय प्रत्याशी अनिल सेठिया, हासभा पर्यवेक्षक प्रकाश लोढ़ा व संजय बांठिया ने नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। नए अध्यक्ष मांडोत ने सभी के सहयोग से, पूर्ण निष्ठा के साथ संघ व समाज हित में कार्य करने का वचन दिया। संगठन मंत्री चंद्रेश चिप्पड़ ने धन्यवाद दिया।

जीभ का घाव वर्षों तक नहीं भरता, हमेशा मधुर बोले : आचार्यश्री कुलबोधिसूरीश्वर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के वेपेरी स्थित विमलाचल अपार्टमेंट में सोमवार प्रातः आचार्यश्री कुलबोधिसूरीश्वरजी का मंगलमय पदार्पण हुआ, जहां संघजनों ने भावभीना स्वागत किया। इस अवसर पर आचार्यश्री ने सुखी जीवन की तीन चाबी विषय पर अत्यंत मार्मिक, प्रेरणादायी एवं जीवनोपयोगी प्रवचन प्रदान किए। आचार्यश्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि यदि जीवन को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है तो तीन विशेष चाबियों को जीवन में धारण करना आवश्यक है। पहली चाबी बताते हुए उन्होंने कहाठीक ढंग से रहना सीखो। उन्होंने वर्तमान आधुनिक जीवनशैली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज इंसान पक्षी की तरह आकाश में उड़ना और मछली की तरह पानी में तैरना तो सीख गया, लेकिन धरती पर सही ढंग से रहना नहीं सीख पाया। उन्होंने प्रेरणा देते हुए कहा कि व्यक्ति को घर में मालिक की तरह नहीं, बल्कि मेहमान की तरह रहना चाहिए। मेहमान की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शिकायत नहीं करता। जो मनुष्य जीवन में शिकायत छोड़ देता है, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ इंसान बनता है।

आचार्यश्री ने कहा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जिसे किसी से शिकायत न हो और जिससे

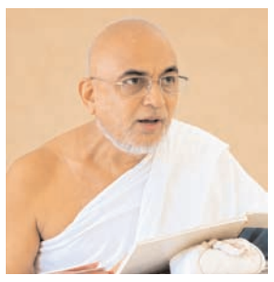

किसी को शिकायत न हो। उन्होंने दैनिक जीवन के छोटे-छोटे व्यवहारों में भी संतोष एवं सहजता अपनाने का संदेश दिया। दूसरी चाबी बताते हुए आचार्यश्री ने कहा ठीक ढंग से कहना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार व्यक्ति की कटु वाणी पूरे वातावरण को अशांत कर देती है। जीभ से दिया गया घाव वर्षों तक नहीं भरता। इसलिए व्यक्ति

विमलाचल अपार्टमेंट में प्रेरणादायी प्रवचन

को संभलकर बोलना चाहिए, क्योंकि पिस्तौल से निकली गोली और जुबान से निकली बोली कभी वापस नहीं आती।उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति कहां, कब, क्यों, कैसा और कितना बोलना है, इन पांच बातों का ध्यान रखे, तो जीवन में अधिकांश विवाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

तीसरी चाबी बताते हुए आचार्यश्री ने कहा जीवन में सहन करना सीखो। उन्होंने कहा कि आज सुविधाएं और शक्ति बढ़ी हैं, लेकिन सहनशक्ति कम होती जा रही है। याद रखिए, गुलाब पाने के लिए कांटों को सहन करना ही पड़ता है। संसार और अध्यात्म, दोनों क्षेत्रों में बिना सहन किए किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आज समाज में हर संबंध में सहनशीलता का अभाव दिखाई देता है। बच्चे माता-पिता का, विद्यार्थी गुरु का, बहू सास का और कर्मचारी मालिक का सहन करने को तैयार नहीं है। यदि जीवन में सहनशीलता आ जाए तो परिवार, समाज और आत्मा तीनों में शांति स्थापित हो सकती है।

अंत में आचार्यश्री ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि यदि व्यक्ति इन तीन चाबियों को जीवन में उतार ले, तो वह निश्चित रूप से सुखी जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है।

चेन्नई एवं कामराजर पोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कारों के निर्यात में स्थापित किया नया रिकॉर्ड

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण व कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 107 मिलियन मीट्रिक टन माल का परिचालन किया है। दोनों बंदरगाहों ने अपने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के 103.37 मिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष एस. विश्वनाथन व कामराजर पोर्ट लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. इरेन सिंथिया ने यहां शुक्रवार को चेन्नई पोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों बंदरगाहों के वार्षिक निष्पादन की जानकारी देते हुए कहा कि यदि दोनों पोर्ट के सामूहिक प्रदर्शन को देखा जाए तो हर अस्सी सेकंड में एक कार का निर्यात किया गया है।

इसके साथ ही चेन्नई पोर्ट ने 57.90 मिलियन मीट्रिक टन तथा कामराजर पोर्ट ने 49.08 मिलियन मीट्रिक टन माल का संचालन किया। चेन्नई पोर्ट ने कंटेनर, कच्चा तेल, कार व क्लीन कार्गो श्रेणी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जिसके परिणाम स्वरूप कंटेनर संचालन 1,905,658 टीईयू तक पहुंचा, जो पहली बार 1.9 मिलियन के पार गया। कच्चे तेल की हैंडलिंग 11.44 मिलियन मीट्रिक टन रही। कार निर्यात में 204,165 इकाई दर्ज हुई, वहीं फर्टिलाइजर कार्गो में 78.4% की बढ़ोतरी के साथ 396,000 मीट्रिक टन का आंकड़े को पार किया। कामराजर पोर्ट ने कोयला संचालन में 25.72 मिलियन मीट्रिक टन का आंकड़ा पार किया। कंटेनर संचालन 700.39 टीईयू रहा। कारों की हैंडलिंग में 18.86% वृद्धि के साथ 191,825 इकाई दर्ज की गई। दोनों पत्तनों की औसत वेसल टर्न-अराउंड टाइम में सुधार दर्ज हुआ। चेन्नई पत्तन में यह 44.72 घंटे रहा, वही कामराजर पोर्ट में 43.27 घंटे रहा।

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष एस विश्वनाथन ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में वित्तीय उपलब्धियों के तहत दोनों पत्तनों की संयुक्त परिचालन आय 2400 करोड़ रुपए से अधिक रही। चेन्नई पोर्ट ने 1,185.01 करोड़ रुपए की आय व 434.29 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस प्राप्त किया है। वही कामराजर पोर्ट ने 1239.15 करोड़ रुपए की आय व 596.03 करोड़ रुपए का सर्वाधिक लाभ अर्जित किया। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दोनों पोर्ट प्राधिकरणों ने कनेक्टिविटी क्षमता, संवर्धन डिजिटलीकरण द ग्रीन इनिशिएटिव पर निवेश राजी रखा हुआ है। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस के तहत प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटलीकरण से व्यापार में नब्बे प्रतिशत तक दस्तावेजीकरण कम हुआ है । दोनों पत्तनों ने क्षेत्रीय विकास व समुदायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए निरंतर प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने की मंशा जाहिर की है।

मंगलापुरम के निःशुल्क नेत्र शिविर में 111 लोग हुए लाभान्वित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय महावीर इंटरनेशनल चेन्नई नॉर्थ टाउन द्वारा महावीर इंटरनेशनल चेन्नई मेट्रो के सहयोग से रविवार को मंगलापुरम सेम्मतम्मन कोइल में निःशुल्क नेत्र शिविर शिविर का आयोजन संपतराज शांतिलाल आबड परिवार के सौजन्य से किया।

अग्रवाल आई हास्पिटल की टीम द्वारा 111 लोगों की नेत्र जांच हुई तथा 64 जनों को चश्मे बना कर दिए जाएंगे। 10 जनों को मोतियाबिंद सर्जरी अग्रवाल आई हास्पिटल में निशुल्क करवाई जाएगी। शिविर में अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानचंद कोठारी, चेन्नई मेट्रो से सचिव दिलीप मेहता, नेत्र शिविर डायरेक्टर नरेश खींचा सहित नार्थ टाउन से चेयरमैन शांतिलाल चौधरी, वाइस चेयरमैन महावीर खींचा, सचिव महावीर सबदड़ा, आदि सदस्योह ने सेवाएं प्रदान की।

'सामायिक' की साधना करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता : डॉ समकितमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के सदाशिवनगर स्थित बागरेचा निवास पर अपने दैनिक प्रवचन में डॉ समकितमुनिजी ने जन्म-मृत्यु के शाश्वत सत्य, धन को बांटने की कला और जीवन की अनिश्चितता विषय पर प्रवचन दिया। मुनिश्री ने उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का बोध कराते हुए कहा कि यह कटु सत्य है कि इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम यहाँ से 'खाली हाथ' ही लौट जाओ। जब तुमने इस संसार में जन्म लिया था, तब तुम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी, लेकिन अब अपना जीवन ऐसे जियो, अपने कर्म ऐसे महान बनाओ कि जब तुम्हारी विदाई का क्षण आए, तो दुनिया रोए और तुम 'मुस्कुराते' हुए इस संसार से विदा लो। रोते-रोते दुनिया को अलविदा मत कहना, अपनी आत्मा के लिए पुण्य की इतनी कमाई अवश्य कर लेना कि अंतिम सफर में तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान हो। इंसान की परिग्रह की अंधी दौड़ पर गहरा प्रहार करते हुए संतश्री ने कहा, इंसान पूरी जिंदगी केवल धन, संपत्ति और साधन 'बटोरने' में लगा रहता है। लेकिन याद रखो, एक समय आने पर जो कुछ भी तुमने बटोरा है, उसे 'बांटना' भी सीखो। जिस इंसान को अपनी संपत्ति और अपना समय शुभ कार्यों में बांटने की कला नहीं आती, उसका मोक्ष कभी संभव नहीं है। केवल 'एकत्र' करने में यकीन मत रखो, क्योंकि कफ़न की कोई जेब नहीं होती। धन की सार्थकता उसे बाँधकर रखने में नहीं, बल्कि उसे सत्कर्मों में प्रवाहित करने में है।ङ्क सफल जीवन और सफल मरण का वास्तविक अर्थ समझाते हुए मुनिश्री ने कहा कि असली सफल जीवन वह नहीं जिसमें तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, बल्कि सफल जीवन वह है जो आरंभ-परिग्रह को कम करके 'शुभ भावों' में बीते। प्रतिदिन अपने भीतर झांककर 'सामायिक' की साधना करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मुनिश्री ने कहा कि हम दिन-रात केवल अपने घर, परिवार, व्यापार और दुनियादारी की चिंताओं में घुले जा रहे हैं, लेकिन क्या कभी एकांत में बैठकर तुमने 'स्वयं' की चिंता की है? इस पूरी दुनिया का कल्याण करने से पहले अपना खुद का कल्याण करो। मुनिश्री ने जीवन जीने का एक अमोघ और स्वर्णिम सूत्र दिया कि कभी भी किसी 'सत्कार्य' को कल पर मत डालो। जो सुकृत करना है, उसे आज और अभी कर डालो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। अपने जीवन को सदैव दान, शील, तप और शुभ भावों में रमण कराओ। नियम बना लो कि यदि मन में कोई अच्छा विचार आए तो उसे 'तुरंत' कर गुजरना है और यदि कोई बुरा विचार या क्रोध आए, तो उसे 'कल पर टाल' देना है। बेंगलूरु चातुर्मास समिति-2026 की ओर से सदस्यों द्वारा संतश्री के आगामी चातुर्मास मंगल प्रवेश सहित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

उपधान तप से आत्मबल और वैराग्य की भावना जागृत होती है : डॉ. पदमचंद्रमुनि

तप आराधकों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव किए साझा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। आत्म आराधना उपधान प्रथम सोपान मोक्षमाला रोपण की पूर्णाहुति पर गणेशबाग में आचार्यश्री पार्श्वचंद्रजी ने आराधकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सामायिक, स्वाध्याय एवं नवकार मंत्र जाप की निरंतरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

जब धर्म के संस्कार जीवन के स्थायी अंग बन जाते हैं, तभी उपधान तप की वास्तविक पूर्णाहुति मानी जाती है। इस अवसर पर उन्होंने मंगल पाठ भी प्रदान किया। डॉ. पदमचंद्रमुनिजी ने कहा कि उपधान तप आत्मा को संयम एवं आत्मशुद्धि की दिशा में अग्रसर करने वाली आराधना है। यह तप जीव को बाह्य वैभव से हटाकर आत्मिक आनंद की अनुभूति कराता है।अनेक दिनों तक व्रत, सामायिक, स्वाध्याय, जाप, प्रतिक्रमण, तपस्या एवं अनुशासन के माध्यम से आराधकों ने अपने भीतर सहनशीलता, संयम और साधना के संस्कारों को जागृत किया है। उपधान तप आत्मा को कर्मनिर्जरा की ओर प्रेरित करता है।

उपस्थित आराधकों ने संतों एवं आयोजकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए तथा 80 आराधकों ने तेले तप का तथा शेष सभी आराधकों ने उपवास का पारणा किया। अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जयमल जैन श्रावक संघ द्वारा उपधान तप केआयोजन एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उपधान संयोजक राजेन्द्रकुमार नाहर के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

बेंगलूरु शाखा के अध्यक्ष मीठालाल लोढ़ा का संघ के अनेक पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया। प्रचार प्रसार प्रभारी जेके महावीरचंद चोरड़िया ने संतों के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी।

संवेदना ही परमात्मा है और परमात्मा ही संवेदना है : राष्ट्रसंतश्री कमलमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के गंगानगर जैन स्थानक में आयोजित प्रवचन सभा में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रसंतश्री कमलमुनिजी कमलेश ने कहा कि संवेदनाहीन निष्ठुर व्यक्ति कितनी उपासना-साधना कर ले वह आत्मकल्याण में सहयोगी नहीं बन सकता। अहिंसा सम्मेलन को संबोधित मुनिश्री ने कहा कि अंतरमन में उठने वाली संवेदना धर्म का असली प्राण है, साधना का राजमार्ग है और मोक्ष मंजिल को पाने के लिए ऑक्सीजन की भांति उपयोगी है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ लोभ और मोह की पूर्ति न होने पर संवेदना नष्ट हो जाती है, धार्मिक व्यक्ति भी राक्षस शैतान के रूप में बदल जाता है। प्राणी मात्र के प्रति निस्वार्थ भाव से अपना नुकसान सहकर भी जहां संवेदना की धारा प्रवाहित होती है वही सच्चा धर्म है। ङ्कमुनिवर ने कहा कि संवेदना के भाव निर्मित होने पर अपनी आत्मा में निर्मलता का संचार होता है। सद्भाव का निर्माण होता है, कर्मों की जंजीर टूटती है, विश्व पूजनीय बनता है। संवेदना ही परमात्मा है और परमात्मा ही संवेदना है। संवेदना में दीवाना बना हुआ तीर्थंकर बनता है। उन्होंने कहा कि इंसान ही नहीं, पशुओं के अंदर भी संवेदना का संचार होता है। जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की प्राणों की रक्षा करते हैं वह भी इंसान से पहले मोक्ष का अधिकारी बन सकते हैं। इस मौके पर संघ के अमृत दलाल, पिंटू पिछोलिया, हेमंत मेहता, जसवंत गन्ना, सुनील नंदावत, रितेश पामेचा, रूपचंद लोढ़ा आदि ने मानव और पशु के प्रति समान संवेदना भाव से काम करने का संकल्प लिया।

जीतो हुब्बल्ली चैप्टर की साधारण सभा सम्पन्न

हुब्बल्ली/दक्षिण भारत । जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जीतो) हुब्बल्ली चैप्टर फाउंडेशन की साधारण सभा रविवार को सम्पन्न हुई। चेयरमैन अनिल कुमार जैन ने सभी का स्वागत करते हुए चैप्टर में नए सदस्यों को शामिल किया। मुख्य सचिव प्रवीण चौधरी ने चैप्टर की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। अनिल कुमार ने राष्ट्रीय कार्यक्रम 'जेबीएन-360' की सफलता पर खुशी ज़ताई। हॉस्टल चेयरमैन भंवरलाल जैन, हुब्बल्ली के पूर्व चेयरमैन प्रकाश कोठारी ने जीतो गर्ल्स हॉस्टल एंड एज्यूकेशन सेंटर के बारे जानकारी दी। सचिव राजन जैन ने भी आगामी विहार धाम परियोजना के बारे में बताया।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.